twitter.com/divyadelhi | facebook.com/divyadelhi | infodivyadelhi@gmail.com | Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

DD

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | बुधवार, 21 मई, 2025 | वर्षः 12, अंकः 192, पृष्ठः 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में टूटकर गिरा पहाड़

पिथौरागढ़
पिथौरागढ़ जिले में पहाड़ी दरकने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। वाहनों का संचालन ठप होने से सैकड़ों की संख्या में यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर ऐलागाड़ और कुलागाड़ के बीच में सोमवार देर रात विशालकाय चट्टान खिसककर सड़क पर आ गया। इससे वाहनों का संचालन ठप है।

'उत्पादन लागत मानदंड आकलन में मदद करेंगे'

नई दिल्ली
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की प्रमुख रवनीत कौर ने मंगलवार को कहा कि उत्पादन लागत के नए मानदंडों से अधिक सटीक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसे लागू करने के परिणामों को तय करना बहुत आसान होगा।

आईबी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्लीः केन्द्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल एक साल और आगे बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने जा रहा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने उनके कार्यकाल विस्तार को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तपन डेका को कश्मीर में आतंक विरोधी ऑपरेशन का विशेष अनुभव है। 2022 से निदेशक पद पर कार्यरत हैं। डेका खुफिया विभाग में कई तरह की भूमिकाएं निभा चुके हैं। आईबी देश की आंतरिक सुरक्षा और काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम देश में आंतरिक खतरों पर नजर रखना और सरकार को परामर्श देना है।

प्रहलाद जोशी ने डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप किया लॉन्च

नई दिल्ली
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किए।

वक्फ संशोधन कानून पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करने की जरूरत

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की सांविधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले तीन घंटे तक सुनवाई। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि कानून पर रोक लगाने और अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करने की जरूरत है। अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए बुधवार को सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पहचाने गए तीन मुद्दों पर सुनवाई को सीमित करने का अनुरोध किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन मुद्दों में अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। धार्मिक गतिविधि को स्वतंत्र रूप से करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वक्फ कानून का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने दलील दी कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 वक्फों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक गैर-न्यायिक, कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है और इसके अनुसार संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है- एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ। कोर्ट का जवाबः सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि लोग अभी भी खजुराहो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हालांकि इसे एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है।

लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा: कपिल

कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले, हालांकि संपत्ति को एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया था, लेकिन संपत्ति की पहचान वक्फ होने से नहीं बदली और सरकार को हस्तांतरित हो गई। अब ऐसी वक्फ संपत्ति शून्य हो जाएगी और एक बार वक्फ शून्य हो जाने पर लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है और इसके अनुसार संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है- एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ।

'लोग अभी भी खजुराहो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं'

राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार, जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करेगा कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश कपिल सिब्बल और अन्य व

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 19 मई तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा था। पीठ को दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि जजों को दलीलों पर विचार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। मेहता ने कहा कि किसी भी मामले में, केंद्र का एक आश्वासन है कि वक्फ की ओर से उपयोगकर्ता की स्थापित संपत्तियों सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी।

सिविल जज बनने के लिए तीन साल बतौर वकील प्रैक्टिस जरूरी

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सिविल जज जूनियर डिविजन के पद के लिए उम्मीदवार अब सीधे परीक्षा पास कर नियुक्त नहीं हो सकेंगे और उन्हें तीन साल कम से कम बतौर वकील प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि देखा गया है कि जो नए कानून स्नातक न्यायपालिका में नियुक्त होते हैं, उनके चलते कई समस्याएं हुई हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को न्यायपालिका में दाखिल होने के लिए कम से कम तीन साल बतौर वकील प्रैक्टिस करना जरूरी होगा।

अदालती कामकाज का अनुभव मिलना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश की न्यायिक व्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ेगा। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आने से पहले अदालत का अनुभव मिलना बेहद जरूरी है।
सीजेआई ने कहा कि कई उच्च न्यायालयों ने अनुभव किया है कि युवा कानून स्नातकों को न्यायिक पदों पर नियुक्त करने से कई समस्याएं होती हैं। अदालत के कामकाज का प्रैक्टिकल अनुभव न्यायिक व्यवस्था की दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

दिखाना होगा सर्टिफिकेट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस की अवधि नामांकन की तारीख से मानी जा सकती है। अदालत ने

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद, विदेश सचिव ने दी सांसदों को ब्रीफिंग

नई दिल्ली
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मंगलवार को संसद भवन में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद के तहत विभिन्न देशों में जाने वाले तीन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल संसद सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि, भारत-पाकिस्तान संबंध और भारत के पक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह ब्रीफिंग भारत की कूटनीतिक पहुंच को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में अहम रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ नीतियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए

सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और विशिष्ट राजनयिक शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शामिल हैं- शशि थरूर (कांग्रेस), रवि शंकर प्रसाद (भाजपा), संजय कुमार झा (जदयू), बैजयंत पांडा (भाजपा), कनिमोझी (द्रमुक), सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी) और श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना)।

पहला सांसद प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन की यात्रा पर रवाना होगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। गुरुवार को जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा।

कोविड-19: एक बार फिर पैर पसार रहा कोरोना

नई दिल्ली
एशिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। भारत में भी इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और सरकार अलर्ट मोड पर है।
हालांकि अधिकारियों की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेटा के मुताबिक,

भारत में 12 मई से अब तक कोविड-19 वायरस के केवल 164 मामले सामने आए हैं।

नए वैरिएंट ने मचाया कहर
इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर केरल का नाम है। केरल में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज्यादा मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, केरल में इस वक्त कोरोना के 69 मामले एक्टिव हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 44 मामले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 8, गुजरात में 6 और दिल्ली में करीब 3 मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई के केईएम अस्पताल में दो कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई।
दोनों गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एक मरीज को ओरल कैंसर था, जबकि दूसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जूझ रहा था।

भारत-अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण को शीघ्र पूरा करने पर चर्चा की

नई दिल्ली
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक के साथ दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत में तेजी लाने के लिए चर्चा की। पीयूष गोयल व्यापार समझौते की वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्री स्तरीय बैठक के लिए इस समय वॉशिंगटन में हैं। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण में तेजी लाने की दिशा में वाणिज्य सचिव (अमेरिकी वाणिज्य मंत्री) हावर्ड लुटनिक के साथ सार्थक चर्चा हुई। मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के मुख्य वातार्कारों के बीच 22 मई तक विचार-विमर्श होगा। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के मुद्दे पर यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देश इस वर्ष शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की संभावना तलाश रहे हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। उनमें बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम और गैर-शुल्क बाधाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार वार्ता पर चर्चा के लिए मार्च में भी वॉशिंगटन गए थे।

भारत और अमेरिका के अधिकारियों का लक्ष्य व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 90 दिवसीय शुल्क विराम अवधि का लाभ उठाना है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26 फीसदी शुल्क को नौ जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे राहुल गांधी: भाजपा

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन्हें आधुनिक युग का मीर जाफर बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों का उपयोग पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के इर्द-गिर्द झूठी कहानी बनाने के लिए किया जा रहा है। मालवीय ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक ग्राफिक साझा किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, राहुल गांधी नए मीर जाफर हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं और

राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। मालवीय ने तंज कसा कि राहुल गांधी को निशान-ए-पाकिस्तान मिलना चाहिए, जो पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों का उपयोग पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भारत के खिलाफ झूठी कहानी बनाने के लिए किया जा रहा है। मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं। एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा नेता अमित मालवीय के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था।

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल में 8 माह के निचले स्तर 0.5 फीसदी पर

नई दिल्ली
देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल में सुस्त रहने से आठ महीने के निचले स्तर 0.5 फीसदी पर आ गई है। पिछले साल इसी अवधि में इन उद्योगों में 6.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च में इन बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.6 फीसदी बढ़ा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में कच्चे तेल, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई है। इससे पहले प्रमुख उद्योगों की कम वृद्धि दर अगस्त, 2024 में दर्ज की गई थी। उस समय इन बुनियादी क्षेत्रों के उत्पादन में 1.5 फीसदी की गिरावट आई थी। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों यानी कोर सेक्टर 40 फीसदी भार होता है।

पुलिस का आधुनिकीकरण जरूरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

कासगंज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कासगंज में 724 करोड़ रुपये की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 25.63 हेक्टेयर में फैली नवनिर्मित अत्याधुनिक पुलिस लाइंस का उद्घाटन भी किया, इसे बनाने में योगी सरकार ने 191 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार कासगंज की पौराणिक और आध्यात्मिक विकास के साथ ही यहां की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2008 में बना कासगंज जिला विकास के लिए तरस रहा था। 2017 से पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा, अराजकता और भ्रष्टाचार ही उनकी पहचान थी। आज

कासगंज विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कासगंज में नवनिर्मित पुलिस लाइंस उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 191 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह पुलिस लाइंस 1,000 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक, अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, ऑडिटोरियम और अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस कर्मी टूटी-फूटी बैरकों में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब हाई-राइज इमारतों में शानदार आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। यह पुलिस लाइंस देश के लिए एक मॉडल है।

यूपी पुलिस सतर्क है, कोई माफिया समानांतर सरकार नहीं चला सकता- योगी
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम की तारीफ करते हुए कहा कि यह पुलिस को सशक्त बनाने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीएम ने कहा कि आज यूपी पुलिस माफियाओं के लिए काल बन चुकी है।
कोई माफिया समानांतर सरकार नहीं चला सकता, न ही गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने की कोशिश करने वालों को अब यमराज का इंतजार करना पड़ता है।

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया- सीएम
सीएम योगी ने कहा कि जैसे देश की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के सेना का आधुनिकीकरण किया, जिसका परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में देखनो को मिला, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया।
उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास मजबूत सेना और बहादुर जवान न होते, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। आज भारतीय सेना दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने की क्षमता रखती है। वैसे ही देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। सीएम योगी ने 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों पर जमकर निशाना साधा।

भाजपा का तंज, 'राहुल बोल रहे पाकिस्तान की भाषा', 'निशान-ए पाकिस्तान' को लेकर पूछा चुभता सवाल

एजेंसी

नई दिल्ली । 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को आधार बनाकर सवाल दाग रहे हैं तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैए पर तंज कसा है। असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल के विवादित पोस्ट के बाद पार्टी की मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। अशोक सिंघल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर को पाक आर्मी चीफ की तस्वीर के साथ जोड़कर शेयर किया। इस तस्वीर के आधे हिस्से में राहुल गांधी का चेहरा और आधे में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का चेहरा लगाया गया है। अशोक सिंघल ने अपने पोस्ट में लिखा, सीमाओं से अलग एजेंडे पर एक।वहीं, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी मंगलवार को सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर कुछ पोस्ट डाले। एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें पाक जनरल की पीठ पर खड़े होकर एक शख्स सरहद के पार देख गिराए गए रफेल की जानकारी मांग रहा है। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरी पोस्ट में सिंघल वाली तस्वीर साझा कर लिखा- यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और

उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय, वे बार-बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए- एक सवाल जिसका जवाब पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में दे चुके हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से चुभता सवाल पूछा कि क्या अब निशान-ए-पाकिस्तान राहुल गांधी को दिया जाएगा? दरअसल, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। हाल ही में सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के उस बयान को लेकर सवाल पूछे थे जिसमें विदेश मंत्री यह कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत होने वाली एयर स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान को सूचना दी थी। हालांकि, राहुल के इन दावों पर 18 मई को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। कांग्रेस नेता ने एक्स पोस्ट पर भी अपनी बात रखी। इसके जवाब में भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया था। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, 'राहुल गांधी की मूर्खता महज आकस्मिक नहीं है, यह भयावह है। वह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।' मालवीय ने भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के एक बयान का वीडियो साझा किया। इसके साथ कहा कि वह भारत के लाभ और विपक्ष के नेता की मंशा को उजागर करने के लिए घई के 11 मई के बयान को दोबारा पोस्ट कर रहे हैं।

शहडोल में जंगल में पत्ती तोड़ने गए तीन ग्रामीणों को हाथियों ने कुचला

एजेंसी

शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी वन परिक्षेत्र के सनौसी और डोडा जंगल में पत्ती तोड़ने गए तीन ग्रामीणों को जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। हादसे के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर क्षेत्र में दशहत का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाथियों के हमले में तीन ग्रामीणों की मृत्यु पर गहन दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के वैध वारिसों को 25-25 लाख रुपये सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सनौसी गांव के उमेश कोल अपनी पत्नी के साथ जंगल में पत्तियां तोड़ने गया था। उसी समय बांधवगढ़ की तरफ से दो जंगली हाथी वहां पहुंच गए। उमेश अचानक हाथियों के सामने आ गया। हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। उमेश की पत्नी जान बचाने के लिए भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने पेड़ से लोगों से मदद के लिए आवाज लगाई। गांव के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हाथी संजय गांधी टाइगर रिजर्व की ओर निकल गए। इसके बाद डिंडौरी जिले के सनौसी से करीब एक किलोमीटर दूर डोडा जंगल में एक महिला की जंगली हाथियों ने कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, 45 वर्षीय महिला देवगनिया बैगा (पत्नी एतु) जंगल में पत्तियां तोड़ रही थी, तभी अचानक वहां हाथी आ पहुंचे और उन्होंने महिला को कुचल दिया। पहले सिर्फ एक ग्रामीण की मौत की जानकारी थी, लेकिन जब पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें दूसरी घटना की जानकारी भी मिली और वे तुरंत डोडा जंगल पहुंचे और जांच शुरू की।

निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी

न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता वहां लागू नहीं होगी, जहां उच्च न्यायालयों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

एजेंसी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में बैठने के लिए 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता को बहाल किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारें सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए सेवा नियमों में संशोधन करके इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सभी राज्य सरकारें नियमों में संशोधन करके यह

सुनिश्चित करेंगी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार के पास कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। इसे बार में 10 साल का अनुभव रखने वाले वकील द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जजों के लिए लॉ क्लर्क के रूप में किए गए काम के समय को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जज चुने जाने के बाद अदालत में सुनवाई से पहले उन्हें एक साल का प्रशिक्षण लेना होगा। न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता वहां लागू नहीं होगी, जहां उच्च न्यायालयों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इसके साथ ही ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं, जो इस मामले के लंबित रहने के कारण स्थगित रखी गई थीं, अब संशोधित नियमों के अनुसार होंगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों के लिए वन रैंक, वन पेंशन के आदेश दिए हैं। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कुछ भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए।

नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, प्रोटोकॉल न मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली । महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नाना पटोले ने लिखा, आपको यह पत्र लिखते समय अत्यंत पीड़ा हो रही है। बहुजन समाज के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपमान किया गया है। एक महाराष्ट्र पुत्र के रूप में उनका मुंबई में सत्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त की उपस्थिति अपेक्षित थी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अंततः मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में यह टिप्पणी की कि मेरे इस कार्यक्रम में इन अधिकारियों को आने की योग्यता नहीं लगती, तो यह विचार उन्हें स्वयं करना चाहिए। यह वक्तव्य अत्यंत दुखदायक है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने ही सुपुत्र का सम्मान करने में विफल रही है। उन्होंने आगे लिखा, न्यायमूर्ति भूषण गवई डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों के अनुयायी हैं, इस कारण उनके साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया ऐसा संदेह संपूर्ण महाराष्ट्र में व्यक्त किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्मान के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोटोकॉल की अवहेलना की है। पटोले ने अंत में विनम्र अपील की। कहा- यह अपमान केवल भूषण गवई का नहीं, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का भी है। इस अपमान के लिए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। आपकी कार्रवाई से भविष्य में कोई भी सरकार और अधिकारी किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का अपमान करने का साहस नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचेंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं में उत्साह

बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

एजेंसी

बीकानेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर दौरे पर होंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहली तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की और बाद में कहा कि कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह दिखाई दे रहा है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जहां पर व्यवस्थाएं कम हो रही हैं उसका विस्तार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी दी। उन्?होंने कहा कि मां करणी की कृपा से हम सफल हुए। ऑपरेशन सिंदूर

की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सेना का काम सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारा कोई जवान हताहत नहीं हुआ, हालांकि पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर घुसकर हमला करने की कोशिश की लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की बस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। सेना ने उन आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया जो कंधार हमले में भी शामिल थे। इस दौरान कई आतंकियों ने यहां तक कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में परिवार के साथ मैं भी मारा जाता। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से सामान्य हवाई यात्राएं चालू करवाई, उसमें भी उन्होंने युद्धक विमान निकाल लिए। भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए कई देशों से गिड़गिड़ाया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के अधिकारियों से कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते है, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने कुछ शर्ते भी रखी कि हमें बचे हुए आतंकवादियों का समर्पण चाहिए, आप आतंकवाद का कभी संरक्षण नहीं करोगे।

मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर : मायावती

एजेंसी

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मंगलवार को मदरसों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला गैरजरूरी और अनुचित है।

उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर। इसके साथ ही मायावती ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के स्कूलों में 22 लाख बच्चों के एडमिशन में इस साल गिरावट आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा के महत्व और जरूरत पर उचित ध्यान देना जरूरी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक तीन पोस्ट किए। बसपा प्रमुख मायावती ने पहले पोस्ट में लिखा, यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किंतु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट सरकारी स्कूल व्यवस्था की

ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिंतनीय। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी।दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा, फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला गैर-जरूरी व अनुचित।

ब्रजेश पाठक के डीएनए पर बात करना सपा के नैतिक पतन को दर्शाता है : नरेंद्र कश्यप

लखनऊ । अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जारी डीएनए विवाद को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक के डीएनए के बारे में बात करना सही नहीं है। मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे विवाद पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, ÷डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना और अपमानजनक टिप्पणी करना, खासकर उनके डीएनए के बारे में, समाजवादी पार्टी में नैतिक पतन के उस स्तर को दर्शाता है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं समाजवादी पार्टी के इन कार्यों और शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा, मेरी समाजवादियों को सलाह है कि वे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा पाएंगे।÷ राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा, पूरे देश और यहां तक कि दुनिया ने हमारी तीनों सेनाओं के प्रयासों की प्रशंसा की। सेना को कार्रवाई की पूरी आजादी देकर और मजबूत कूटनीति के साथ उनका समर्थन करके प्रधानमंत्री ने भारत की सैन्य शक्ति का स्पष्ट रूप से एहसास कराया।

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बटाला में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़

एजेंसी

चंडीगढ़ । पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बटाला पुलिस ने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे। ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े हुए थे और इनका मास्टरमाइंड मनिंदर बिल्ला और मन्नू अगवान था। बटाला पुलिस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है। पुलिस के एक्स हैंडल के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जतिन कुमार उर्फ रोहन, बरिंदर सिंह उर्फ साजन, राहुल मसीह, अब्राहम उर्फ रोहित, सोहित और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक 30 बोर पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी बटाला में एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला करने की कोशिश कर चुके थे। गिरफ्तार आतंकियों को पुर्तगाल स्थित मनिंदर बिल्ला और बीकेआई मास्टरमाइंड मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। मन्नू अगवान ने हाल ही में अमेरिका में हैप्पी पासियन की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशनल चार्ज संभाला था। गिरफ्तार आतंकियों में से एक जतिन कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे राज्य में आतंकी नेटवर्क को बेअसर करने और शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

प्रतिबद्ध हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार, छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली

एजेंसी

मुंबई । वरिष्ठ एनसीपी नेता और समता परिषद के संस्थापक छगन भुजबल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को एक समारोह में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में हुआ। समारोह के बाद भुजबल ने कहा, ÷मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ-साथ सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, समता

परिषद के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अब तक मुझे प्यार और स्नेह दिया है। भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मिलने की उम्मीद है, उन्होंने इससे पहले इस विभाग की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे (2019-24) के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों में उठाई थी। भुजबल तब काफी समय से नाराज चल रहे थे। दरअसल, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, लेकिन मंत्री पद नहीं दिया था। आहत भुजबल ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर की थी और कहा था कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ओबीसी मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के बावजूद उनके बारे में विचार नहीं किया गया।

इसके बाद उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया।

परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन का निधन

एजेंसी

चेन्नई। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन का मंगलवार को तमिलनाडु के उधगमंडलम में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। देश के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के प्रमुख वास्तुकार डॉ. श्रीनिवासन ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) में करियर सितंबर 1955 से शुरू किया और पांच दशकों से भी ज्यादा समय तक अपनी सेवा दी थी।उन्होंने डॉ. होमी

भाभा के साथ मिलकर देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में काम किया, जो अगस्त 1956 में शुरू हुआ था। वष्र 1959 में उन्हें देश के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए प्रधान परियोजना इंजीनियर नियुक्त किया गया। वर्ष 1974 में वे डीएई के पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग डिवीजन के निदेशक बने और एक दशक बाद न्यूक्लियर पावर बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला। वर्ष 1987 में डॉ श्रीनिवासन को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। उसी साल वे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के संस्थापक अध्यक्ष भी बने। उनके कार्यकाल में उल्लेखनीय विस्तार हुआ और उनके मार्गदर्शन में 18 परमाणु ऊर्जा इकाइयां विकसित की गई, जिनमें सात चालू हो गई थीं और सात निर्माणाधीन थीं। इसके अलावा, चार योजना चरण में थीं। परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए डॉ. श्रीनिवासन को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

निजी बस के खड़ी लॉरी से टकराने से चार लोगों की मौत, कई घायल

एजेंसी

विकाराबाद। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मंगलवार तड़के एक निजी बस के खड़ी लॉरी से टकरा जाने से चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।पुलिस ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल के चेनवेल्ली गांव के 60 लोगों का एक समूह परिगी में एक डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद बस से घर लौट रहा था, तभी परिगी मंडल के रंगपुर के पास बीजापुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई।एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने परिगी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को बाद में बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए हैदराबाद के उस्मानिया सरकारी सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

'देश की जीत पर कुछ लोगों को दुर्भावना के गीत गाना पसंद', भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तृणमूल पर तंज

एजेंसी
नई दिल्ली। 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने के इरादे से गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान का नाम वापस लेने पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों को देश की जीत पर दुर्भावना के गीत गाने की आदत हो गई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने समाचार एजेंसी से कहा कि तृणमूल देश की जीत पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशवासी सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं। भारत के लोगों को सेना और पीएम मोदी पर विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज देश का यही मूड है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर पाकिस्तान को जवाब दिया। पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम को देखा है। हमारे यहां से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करेगा। लेकिन, तृणमूल को इसमें भी राजनीति ही नजर आ रही है।

प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 'भाजपा उन लोगों से डरती है, जो उन्हें पसंद नहीं'

नई दिल्ली। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा किसी भी ऐसी राय से कितना डरती है, जो उन्हें पसंद नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों, नौकरशाहों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चरित्र हनन, बदनामी, ट्रोलिंग, उत्पीड़न, गैरकानूनी गिरफ्तारी और किसी भी व्यावसायिक संस्थान के खिलाफ तोड़फोड़ की निंदा करता हूं, चाहे यह कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हो या सरकारी मशीनरी के माध्यम से। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा किसी भी ऐसी राय से कितना डरती है, जो उन्हें पसंद नहीं।

सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत धर्मशाला नहीं : श्रीलंकाई तमिल की शरण याचिका खारिज, कहा- हर किसी को शरण नहीं दे सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में श्रीलंकाई तमिल नागरिक की शरण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां दुनियाभर से आए लोगों को शरण दी जाए। हम पहले से ही 140 करोड़ की आबादी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण देना संभव नहीं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की अपील खारिज करते हुए की। दरअसल, याचिकाकर्ता को 2015 में तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच ने दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन लिट्टे से जुड़ा हुआ है। 2018 में निचली अदालत ने उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी क्क के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी। 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने उसकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया और आदेश दिया कि सजा पूरी होते ही उसे भारत छोड़ना होगा। साथ ही, निर्वासन तक उसे शरणार्थी शिविर में रखा जाएगा।

धानमंत्री 22 मई को बिजनौर के रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बिजनौर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंस के जरिए करेंगे। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। भारत योजना के तहत स्टेशन बिजनौर का 22 मई को शुभारंभ किया जाएगा। स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था, दो एटीवीएम मशीन, कैटरिंग स्टॉल की व्यवस्था, एसी सुविधाओं से लैस दो वेटिंग रूम, फुट ओवर ब्रिज व फ्लाइट लाइटों की सुविधा दी गई है। स्टेशन की बिल्डिंग भी शाम को रंग बिरंगी लाइटों से रोशन होती है। सीएमआई जितेन्द्र कुमार ने बताया कि 22 मई को पीएम नरेन्द्र मोदी रेलवे स्टेशन की नवीन बिल्डिंग का उदघाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिजनौर समेत 103 अमृत भारत स्टेशनों का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे।

नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम : पीएम मोदी

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया ओसीआई पोर्टल नागरिक-अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, 'उन्नत सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया ओसीआई पोर्टल नागरिक अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।' अमित शाह ने भारतीय मूल के लोगों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए यूजर इंटरफेस के साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के नए पोर्टल का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, नया पोर्टल पिछले दशक में तेजी से हुई तकनीकी प्रगति और पिछली प्रणाली से संबंधित समस्याओं के संबंध में मौजूदा ओसीआई कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है।

अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, 'आज विदेशी नागरिकों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए एक अप-टू-डेट यूजर इंटरफेस के साथ संशोधित ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया गया। नई सुविधाओं में बेहतर कार्यक्षमता, बढ़ी हुई सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव शामिल होंगे।'

ओसीआई योजना 2005 में शुरू की गई थी। इसमें भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (पीआईओ) को ओसीआई के रूप में पंजीकरण करने का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद देश के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिक बनने के योग्य थे या उनके वंशज थे। कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं, वह ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से यूसुफ पठान का नाम वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण : केसी त्यागी

एजेंसी
नई दिल्ली। 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के इरादे से भारत की ओर से विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से तृणमूल सांसद यूसुफ पठान के नाम वापस लेने पर जेडीयू नेता के.सी. त्यागी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। के.सी. त्यागी ने समाचार एजेंसी से कहा कि सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आतंकवादी सोच को एक्सपोज करेगा। इसमें राजनीति करना बिल्कुल गलत है। गृह मंत्रालय की ओर से देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की पहचान के लिए एक महीने की समयसीमा तय करने पर जेडीयू नेता ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यह बिल्कुल सही फैसला है। वर्तमान में इसकी जरूरत भी है। इसका उद्देश्य अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों को रोकना है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की ओर से दिए नामों को स्वीकृति नहीं मिलने पर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि

कांग्रेस पार्टी काफी समय से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राजनीति कर रही है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद देश का पक्ष रखेंगे। इसमें नाम नहीं, बल्कि विषय महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई की ओर से एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के सभी आयोजनों से हटने के फैसले की आशंकाओं के बीच के.सी. त्यागी ने कहा, बीसीसीआई को बिल्कुल ऐसे फैसले लेने चाहिए, मैं इसका स्वागत करूंगा। जब युद्ध, नफरत और बदले की भावना हो, तो खेल नहीं चल सकता।

सिंधु जल संधि रद्द कर पीएम मोदी ने ऐतिहासिक अन्याय समाप्त किया : शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान और सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर एक ऐतिहासिक अन्याय समाप्त कर दिया है।शिवराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान यह सोच रहा था कि तुर्की और चीन के ड्रोन तथा मिसाइलों से भारत डर जाएगा, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें 'खिलौनों की तरह' मार गिराया। उन्होंने कहा, 'आज हमारे बच्चे पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन के मलबे से खेल रहे हैं।' उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सिर्फ तीन दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जब 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को

सौंप दिया और साथ में 83 करोड़ रुपए भी दिए थे, जो वर्तमान में करीब 5,500 करोड़ रुपए के बराबर है। उन्होंने कहा कि उस समय भारत के जल विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इस संधि का विरोध किया था। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में इसका विरोध किया था, लेकिन नेहरू ने विशेषज्ञों की बातों को दरकिनार कर देश के हितों के खिलाफ फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इस अन्याय को समाप्त किया है। अब यह पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि हमारे देश के किसानों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उन्हें भरोसा दिलाया कि अब भारत का पानी भारत के काम आएगा।

स्कूली बच्चों को इसी वर्ष से एआई शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे: धर्मेंद्र प्रधान

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में हम इसी वर्ष से देशभर के स्कूली बच्चों को एआई शिक्षा से जोड़ने का प्रयास शुरू करेंगे। उन्होंने देश के शिक्षाविदों से आग्रह किया कि वे? आयु-उपयुक्त, एआई-एम्बेडेड पाठ्य-पुस्तकें तैयार करें। उन्होंने कहा, हमें वृद्धिशील सुधार नहीं, बड़ी छलांग चाहिए। इसके लिए एआई/एमएल जैसी तकनीक को भारतीय भाषाओं से जोड़ना अनिवार्य है ताकि यह बल गुणक बने।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 13 भारतीय भाषाओं में विकसित नई प्राइमर पुस्तक एवं विशेष मॉड्यूल्स का भी विमोचन किया। इन 13 भाषाओं में कश्मीरी (फारसी-अरबी लिपि), सिंधी (देवनागरी), सिंधी (फारसी-अरबी लिपि), कश्मीरी

(देवनागरी), बाल्टी, संथाली, ज़ेमे, उर्दू, संगतम, लाई (पावी), गोंडी-तेलुगु, भीली (वागड़ी) और चोक्रि शामिल हैं। इसके साथ कुल प्राइमर की संख्या अब 117 हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज के कार्यक्रम को तमिलनाडु में पली-बढ़ी बिहार की जिया?कुमारी?को समर्पित किया। जिया ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा में तमिल भाषा में 93 अंक लाकर उन लोगों की आंखें खोल दीं, जो देश में भाषा के आधार पर विभाजन बोने का प्रयास करते है। ऐसे समय में जब भारत अपनी विरासत के साथ चहुंमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है, यह आयोजन और भी प्रासंगिक हो जाता है।

भारत को विकसित राष्ट्र तथा दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें कम-से-कम कक्षा 8 तक की शिक्षा मातृभाषा में करवाने की दिशा में तेज गति से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई हमारे बच्चों की प्रारम्भिक समझ को मजबूत बनाती है। आज जब बाजार की ताकतें भी भारतीय भाषाओं को मजबूत कर रही है। हमें अपनी भाषाओं के संवर्धन के लिए पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर सोचना होगा।

गृह मंत्रालय की नई पहल ई-जीरो एफआईआर से अपराधियों को पकड़ने में आएगी तेजी : अमित शाह

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने अभूतपूर्व गति से अपराधियों को पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, यह नया सिस्टम, एनसीआरपी या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः एफआईआर में परिवर्तित करेगा। शुरू में यह 10 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी, और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को

मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'साइबर सुरक्षित भारत' के विजन को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की हाल की समीक्षा बैठक में साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को गंवाए हुए धन को वापस हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पहल को लागू करने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 ने साइबर वित्तीय अपराधों से संबंधित शिकायतों की आसान रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाया है।

शुरू की गई नई प्रक्रिया में आई4सी के एनसीआरपी सिस्टम, दिल्ली पुलिस के ई-एफआईआर सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) का एकीकरण शामिल है। अब एनसीआरपी और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय हानि से संबंधित शिकायतें अपने-आप दिल्ली के ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होंगी।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- 'सिंदूर' का सौदा होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर केंद्र सरकार और विदेश मंत्री से सवाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद मीडिया एजेंसियों को बताया कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, युद्ध सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि राजनीति के रणनीतिकारों द्वारा भी लड़े जाते हैं। सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम करती हैं, तो युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की भी होती है, जो राजधानी में बैठे होते हैं। इन तमाम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो सेना के पराक्रम को या तो बूस्ट कर सकती है या सेना के पराक्रम को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान पर कुछ सवाल पूछे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग-अलग देशों में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। ट्रंप ने एक बहुत खौफनाक बात यह भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया यानी 'सिंदूर' का सौदा होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि अमेरिका और चीन के पास पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और भाजपा के नेताओं के ऐसे कौन से राज हैं, क्योंकि इनका कभी अमेरिका और चीन के आगे मुंह नहीं खुलता।

विदेश सचिव ने संसदीय समिति को बताया, संघर्ष में पाक की ओर से नहीं मिले 'परमाणु संकेत'

एजेंसी
नई दिल्ली। विदेश मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के समक्ष विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव पारंपरिक दायरे में ही रहा और पाकिस्तान की ओर से कोई परमाणु संकेत (न्यूक्लियर सिग्नलिंग) नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार, मिस्री ने समिति को बताया कि सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय पूरी तरह से द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। उनका यह जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के संदर्भ में भी था। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। इसमें रविशंकर प्रसाद, अभिषेक बनर्जी, राजीव शुक्ला, दीपेन्द्र हुड्डा, असदुद्दीन ओवैसी, अपराजिता सारंगी और अरुण गोविल सहित अन्य शामिल हुए। यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत-पाक के बीच बढ़े तनाव के संदर्भ में बुलाई गई थी। बैठक में सदस्यों ने विदेश सचिव से कई सवाल किए। साथ ही भारत को हुए नुकसान पर भी सवाल हुए। हालांकि विदेश सचिव ने कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। विदेश मंत्री एस.

जयशंकर के कथन पर उठे सवालों पर मिस्री ने समिति को बताया कि जयशंकर के बयान को 'गलत' अर्थ में नहीं देखना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने यह भी पूछा कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान चीनी सैन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इस पर विदेश सचिव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को कुशलता से निशाना बनाया। बैठक के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने सोशल मीडिया पर मिस्री की आलोचना पर एकमत होकर विरोध जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की निंदा करते हुए विदेश सचिव की पेशेवर कार्यशैली की सराहना की। उल्लेखनीय है कि 6 मई की रात को शुरु होने के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आपसी समझौता किया था।

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून क़ासमी ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात

एजेंसी
हरिद्वार। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ़्ती शमून क़ासमी ने शिक्षविदों, बुद्धिजीवियों और सूफियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने रक्षा मंत्री को बताया कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का विवरण शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के निर्देश में भारत की तीनों सेनाओं का ऐसा कदम है, जिससे पूरी दुनिया हतप्रभ है। क़ासमी ने रक्षा मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों और पाकिस्तान की बमबारी में मारे गए जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड के नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया जाएगा।

उपराष्ट्रपति बोले- प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मैं भी भुक्तभोगी

एजेंसी
नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी इस लापरवाही के शिकार रहे हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाल में प्रोटोकॉल को लेकर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान 'द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड (विद आर्टवर्क्स)' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में दिया। इस पुस्तक का संपादन विजय हंसारिया ने किया है। कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित हुआ था, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कानूनी क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा, आज सुबह मुझे याद दिलाया गया कि प्रोटोकॉल केवल व्यक्ति नहीं बल्कि उस पद की गरिमा का सवाल है। हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह बात देश के लिए कही थी और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान

खींचा। उन्होंने व्यथा जाहिर करते हुए कहा, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं। मैं जब इस पद से हटूंगा, तो अपने उत्तराधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करूंगा कि उनकी तस्वीर वहां हो। धनखड़ ने सिविल सेवकों की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई बार नियमों की अनदेखी जानबूझकर होती है, जो गलत परंपरा की शुरुआत करती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह केवल उनके सम्मान की बात नहीं है, बल्कि पद की गरिमा से जुड़ा मसला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसे मामलों में सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने अंत में दोहराया कि लोकतंत्र में हर पद का सम्मान जरूरी है। प्रोटोकॉल न केवल औपचारिकता है बल्कि यह संस्थागत संतुलन और मर्यादा का प्रतीक है।

प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का हनन: मौलाना महमूद असद मदनी

एजेंसी
नई दिल्ली । जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मामले की न्याय के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि प्रोफेसर अली खान का बयान, जो कि मेरे भी संज्ञान में है, देशद्रोह या अपमान के रूप में पेश करना समझ से परे है। जहां तक आलोचना या असहमति का सवाल है, इसकी अनुमति है, भले ही इसका सरकार से ही लेना-देना क्यों न हो। यह एक स्थापित तथ्य है कि सरकार या देश के किसी वर्ग या संगठन से असहमति, देश का विरोध करने के समान नहीं है। मौलाना मदनी ने सरकार और प्रशासन के दोहरे मापदंड का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री कर्नल कुरैशी को %आतंकवादियों की बहन कहते हैं, जिसके लिए अदालत उन्हें फटकार लगाती है, लेकिन सरकार या पार्टी द्वारा अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर अली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उक्त मंत्री का बयान देश की एकता का अपमान है। यह दृष्टिकोण न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति लोगों में अविश्वास को बढ़ावा देता है। मौलाना मदनी ने कहा कि न्याय की रक्षा करने वाली संस्थाओं को यह समझना चाहिए कि कानून का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भय या चुप्पी के बजाय विचारों का सम्मान करने से स्थापित होती है। मौलाना मदनी ने जोर देते हुए मांग की है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और प्रोफेसर अली खान की बिना शर्त रिहाई के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएं। हरियाणा स्थित अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले अली खान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया।

संपादक की कलम से

सेना और न्यायपालिका के सम्मान का सवाल

देश के नए मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई अपना पद संभालने के बाद रविवार को पहली बार अपने गृहराज्य महाराष्ट्र पहुंचे थे। लेकिन उनकी अगवानी के लिए महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन्द्र भारती, तीनों वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे। यह बात आई-गई हो जाती, अगर खुद जस्टिस गवई इसका जिक्र नहीं करते। क्योंकि मौजूदा दौर के मीडिया में ऐसी बातों का जिक्र अब नदारद है। खुद जस्टिस गवई ने इस बात को छोटा मुद्दा ही बताया, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे जाहिर होता है कि यह मामूली अनदेखी नहीं थी।

महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, मैं ऐसे छोटे-मोटे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि महाराष्ट्र के बड़े अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान हैं और उन्हें एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। सीजेआई गवई ने कहा, जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि वो इस तरह की छोटी बातों में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत महसूस हुई ताकि लोग इसके बारे में जानें। इसके आगे उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा होने लगती। ये छोटी-छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी आदेश जारी करने का अधिकार देता है। इसके तहत न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। कुछ समय पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के शक्तिशाली होने के संदर्भ में इस अनुच्छेद को परमाणु मिसाइल कहा था।

बहरहाल, जस्टिस गवई की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद तीनों शीर्ष अधिकारी दादर स्थित चैत्यभूमि पहुंचे, जहां प्रधान न्यायाधीश ने डॉ. बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सीजेआई गवई ने कहा, सीजेआई बनने के बाद मैं पहली बार चैत्यभूमि आया हूं। मैं यहां डॉ. अंबेडकर का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं प्रोटोकॉल को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हूं। मैंने बस इसका जिक्र किया है। जानकारी के लिए बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश जब किसी राज्य का दौरा कर रहे हों, तब उनकी अगवानी और स्वागत से लेकर ठहरने तक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। इसके लिए राज्य के प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित अफसरों को अगवानी के लिए उपस्थित होना चाहिए। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी स्वागत समारोह में उपस्थित हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा घेरा सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से वीआईपी गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायिक या विधायी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो राज्य के प्रमुख न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल का पालन जरूरी माना जाता है।

लेकिन जस्टिस गवई के मुंबई दौरे के शुरूआती पलों में यह प्रोटोकॉल नदारद रहा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के इतने वरिष्ठ अधिकारी इस सामान्य जानकारी से अनभिज्ञ होंगे। लेकिन किस वजह से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की अगवानी के लिए उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र सरकार अपने इन अधिकारियों से इस संदर्भ में कोई जवाब-तलब करेगी, या यह बात आई-गई हो जाएगी। क्या जस्टिस गवई की जाति या धर्म का इस प्रकरण से कोई वास्ता है। और सबसे गंभीर सवाल यह कि भाजपा शासित राज्य में ऐसा होने का क्या अर्थ है। क्योंकि इससे पहले भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर गृहयुद्ध करवाने जैसे गंभीर और बेहूदा आरोप लगाए थे। भाजपा ने अपने सांसद की ऐसी धृष्टता पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।

भाजपा के शासन में ही बार-बार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कौन बड़ा है इसकी बहस खड़ी हो रही है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, फिर भी उन्होंने परमाणु मिसाइल जैसा बयान दिया था। निशिकांत दुबे भी ऐसे सवाल उठा चुके हैं। हालांकि मुंबई में जस्टिस गवई ने एक बार फिर कहा है कि न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और न ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सुप्रीम है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है। भाजपा के उठाए सवालों का जवाब मुख्य न्यायाधीश के इस बयान में मिल जाता है।

अब भाजपा को भी देश की सत्ता पर काबिज होने और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों उसके राज्य में मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रोटोकॉल निभाने में अनदेखी की गई। सेना और न्यायपालिका इन दो संस्थाओं की साख देश में तमाम राजनैतिक लाभालाभ से परे बनी रही है। आम जनता का इन दोनों पर ही अटूट विश्वास रहा है। लेकिन क्यों भाजपा के शासन में ही सेना को लेकर भी अभद्र टिप्पणियां हुईं और उसमें भी जाति, धर्म, प्रांत की बातें आ गईं, वही रवैया क्या अब न्यायपालिका को लेकर भी भाजपा बरत रही है।

क्या हरी मिर्ची खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है? जानें यहां

हरी मिर्च हरी मिर्ची के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. हरी मिर्च में विटामिन उ, विटामिन अ, बीटा-कैरोटीन, आयरन और पोटैशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैप्सैसिन नामक एक खास तत्व होता है, जो इसे तीखा बनाता है. यही कैप्सैसिन हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है.

कई शोध बताते हैं कि हरी मिर्च में मौजूद कैप्सैसिन दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है. यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (छऊछ) को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (लऊछ) को बनाए रखने में सहयाता करता है. साथ ही, यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और रक्त धमनियों में जमे फैट को कम करने में मदद कर सकता है. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. इसके अलावा हरी मिर्च में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं. सूजन भी दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह मानी जाती है.

कैंसर से लड़ने में मददगार

हरी मिर्च सिर्फ हार्ट से संबंधित समस्याओं को ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मददगार होता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं. फ्री रेडिकल्स वे हानिकारक तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं. हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैप्सैसिन कुछ प्रकार के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक सकता है. खासकर प्रोस्टेट, पेट और फेफड़ों के कैंसर में इसके फायदे देखे गए हैं.

भीतर के दुश्मनों के खिलाफ सख्ती-चौंकसी बढ़ानी होगी

- ललित गर्ग-

पाकिस्तान भारत के अनेक लालची, शानोशौकत के आकांक्षी, देशद्रोही एवं देश के दुश्मन लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ऐसे ही कुछ देश विरोधी तत्वों का पदार्फाश होना चौंकाता भी है एवं चिन्ता में भी डालता है। ऐसे ही तत्वों में एक नाम है ज्योति मल्होत्रा, उस पर आरोप है कि वह न केवल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने पाक खुफिया एजेंसी के एजेंटों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी साझा कर रही थीं, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भी थीं। वह एक खुफिया एजेंट के रूप में सीमा पार से चलाए जा रहे नेटवर्क का हिस्सा थी। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी पर छिपे गद्दार कितनी भी चालाकी से छिप जाएं, वे कानून की नजरों से नहीं बच सकते। उम्मीद है कि पूछताछ में ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों का खुलासा कर सके। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। हाल ही में लगातार ऐसे अनेक राष्ट्र-विरोधी जासूसों की गिरफ्तारी ने जता दिया कि भारत हर मोर्चे पर देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। ये गिरफ्तारियां अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण एवं यह भी पाक की एक करारी हार ही है।

पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत छह लोगों की खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गयी गिरफ्तारी भारत की सतर्कता एवं सावधानी को तो दशार्ती ही है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस चुनौती भरे समय में भीतर के दुश्मनों की शिनाख्त एवं उनकी धडपकड़ कितनी जरूरी है। ट्रैवल विद जो नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति पर आरोप है कि वह पाक के कई उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी और भारत से जुड़ी गुप्त सूचनाएं पाक तक पहुंचाती थी। पता यह भी चला है कि पाक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात पाक उच्चायोग के एक कर्मचारी दानिश से हुई, जिसके माध्यम से उसकी पहचान आइएसआइ के एजेंटों से हुई। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिये संपर्क में थी। कहते हैं कि उसने एक पाक खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाये और उसके साथ बाली भी गयी थी। ज्योति एवं उसके सहयोगी बेखौफ भारत की अति-संवेदनशील एवं गोपनीय सूचनाओं को पाक से साझा करते हुए देश को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सभी आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे राष्ट्रविरोधी थे। देश की कीमत पर सारे राष्ट्र-मूल्यों एवं निष्ठाओं को ताक पर रखकर धनार्जन की लालसा और मौज-मस्ती का लक्ष्य घिनौना एवं अक्षम्य अपराध है। राष्ट्र को इन विस्फोटक विसंगतियों से बचाना होगा।

भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलकर देश को मुश्किल में डालने का यह कृत्य परेशान एवं चिन्ता में डालने वाला है। बहुत संभव है कि जासूसी कांड में लिप्त ये भारतीय बड़े आर्थिक प्रलोभनों के लालच में पाक एजेंटों के जाल में फंसे हों। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि कैसे कुछ लोग पैसे व शानोशौकत के लालच में देश की सुरक्षा व लोगों का जीवन भी दांव पर लगा सकते हैं? देश के भीतर के ये दुश्मन बाहरी दुश्मनों से ज्यादा घातक एवं नुकसानदेय हैं। पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से ताल्लुक रखने पर पिछले दिनों हरियाणा, पंजाब व यूपी के इन लोगों की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लेकिन इनकी गहन जांच से और भी गंभीर खुलासे होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये एक गंभीर चुनौती है और हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया संस्थाओं को अब इस चुनौती को गंभीरता से लेना होगा। इन लोगों के तार भीतर कहां-कहां जुड़े है, इसका पदार्फाश होना ज्यादा जरूरी है। ये तत्व देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव एवं आम-जनजीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं।

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा की ज्योति कथित तौर पर हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी के संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिये देश से निकाला गया। इस मामले में चल रही जांच से पता चला है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई और उससे पहले पाकिस्तान गई थी। एक से अधिक बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पर खुफिया अधिकारियों की नजर तो थी ही, ज्योति के कई वीडियोज ने भी खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींचा, चाहे वह नयी दिल्ली स्थित पाक दूतावास में इफ्तार की दावत का वीडियो हो, पिछले साल हुए विश्व कप में भारत-पाक मैच में दर्शकों की प्रतिक्रिया वाला वीडियो हो या कश्मीर घूमने आये लोगों पर बनाये गये वीडियो हों। विडंबना है कि पाकिस्तान भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था।

यह खुलासा केवल ज्योति तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके जरिये एक बड़े नेटवर्क का पदार्फाश हुआ है उस पर पाक के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। यूपी के रहने वाले शहजाद और नौमान इलाही पर भी इसी तरह के आरोप हैं। पंजाब में मालेरकोटला के दो लोगों को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा कि क्या इन आरोपियों की सैन्य या रक्षा अभियानों से संबंधित जानकारी तक सीधी पहुंच थी या वे इसे उच्च पदस्थ स्त्रोतों से प्राप्त कर रहे थे? इन बातों का खुलासा होना सुरक्षा एवं सैन्य गोपनीयता की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को गंभीर पूछताछ के बाद कठोर सजा मिलनी चाहिए। दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या बाहर उनके प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर सख्ती के साथ कार्यरत रहनी ही चाहिए। सरकार और खुफिया एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की दिशा में स्वाभाविक ही काम कर रही है। सरकार ने इन गिरफ्तारियों के बाद स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक देशभर में दर्जनों संदिग्धों को निगरानी में लिया गया है और जांच तेज है।

निश्चय ही यह राष्ट्र-विरोधी जासूसों का खुलासा पाक रचित राष्ट्रघाती खेल का छोटा हिस्सा है, पाक सीधा युद्ध की सामर्थ्य एवं ताकत नहीं रखता, इसलिये कभी वह आतंक का सहारा लेता है तो कभी पैसों का प्रलोभन देकर देश के लोगों को खरीदने की कुचेष्ठा करता है। एक छलकपट वाले सूचना युद्ध के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की आईएसआई की साजिश को सख्ती से नाकाम किया जाए ताकि आने वाले समय में और बड़ी मछलियां इस दलदल में पकड़ी जा सकेंगी। पाक तो भारत का शत्रु है और वह सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन देश के अंदर छिपे गद्दार भी भारत के शत्रु हैं। इस तरह के गद्दारों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पाक का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हैं, कश्मीर में भी ऐसे लोग है जो पाक एवं उसके पोषित आतंवादियों का सहयोग एवं समर्थन करते हैं। ऐसे राष्ट्र-विरोधी लोगों एवं आतंकवादियों का सिर कुचलने का, यही सही समय है। केंद्र व राज्य सरकारों, मीडिया और जनता को मिलकर ऐसे तत्वों को बेनकाब करने में मदद करनी चाहिए। पुलिस को आधुनिक उपकरणों के साथ इस बाबत कुशल प्रशिक्षण देना चाहिए। बहरहाल, देश विरोधी तत्वों की निगरानी तेज करना वक्त की जरूरत है

भारत के सिंहासन पर ट्रंप की पादुकाएं!

संजय राऊत

भारत ने पाकिस्तान से युद्ध क्यों किया? युद्ध तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका द्वारा व्यापार बंद करने की धमकी के बाद शस्त्रसंधि करके हम मुक्त हो गए। यह सब पंडित नेहरू ने नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने देश, सेना और जनता के प्रति वफादारी नहीं निभाई। कोई पैष्ठसला किए बिना ही २०२५ के भारत-पाक युद्ध को अपने ५६ इंच के सीनेवाले प्रधानमंत्री मोदी ने समाप्त कर दिया है। मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह मिलकर अब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में ला ही देंगे। लाहौर और कराची में भी घुसेंगे, ऐसी हवा पहले बनाई गई; लेकिन प्रत्यक्ष युद्धभूमि पर इन राजनेताओं ने फुस्की बम की तरह बर्ताव किया। उन्होंने अपनी सेना के उत्साह पर पानी फेर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। घर में घुसकर मारेंगे इस जोश के साथ जब प्रधानमंत्री लड़ाई में उतरे तो देश के सभी विपक्षी दल मोदी के पीछे मजबूती से खड़े हो गए। घर में घुसो और मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसी सभी ने घोषणा की; लेकिन प्रे. ट्रंप द्वारा भारत पर युद्ध रोकने का दबाव डालने के बाद मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों की प्रशंसा की और फिर गरजे, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे। यह बहुत बड़ा मजाक है। प्रधानमंत्री उलझन में हैं। जब उन्हें घर में घुसकर मारने का मौका मिला तो वे पीछे हट गए और अब वे फिर से मारने की बात कर रहे हैं। मोदी की ओर से बहादुरी जैसा कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार के बदले पाकिस्तानी आतंकवादियों को सीधे अभय दे दिया। उन्होंने सेना का मनोबल तोड़ा और पुनः सेना की जीत का जश्न मनाने चले गए। मोदी को अब राष्ट्रहित के लिए दो काम करने चाहिए। पहलगाम हमले का जिम्मेदार मानते हुए गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने का साहस तो दिखाना चाहिए और देश पर दया करते हुए उन्हें भी प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बेइज्जती हमारे देश की इस समय हुई है। इस दौरान हमारा देश काफी अराजकता से गुजरा है। मोदी इंदिरा गांधी को मात देने गए थे; लेकिन वे वी. पी. सिंह और मोरारजी देसाई भी नहीं बन पाए। उन्होंने २६ बहनों के अपमान का बदला नहीं लिया और प्रे. ट्रंप के ऊंट को भारत के तंबू में ले लिया।प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी-बड़ी बातें करके भी कुछ हासिल नहीं किया। अगर उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर के एक गांव पर भी कब्जा कर लिया होता तो भी इस नए महाभारत का कुछ मतलब होता, लेकिन युद्धविराम का श्रेय भी प्रे. ट्रंप ने ले लिया। अब देश को यह अहसास हो गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री के सिंहासन पर प्रे. ट्रंप की पादुकाएं रखकर ये राज कर रहे हैं। मोदी को युद्ध रोकने के बदले में कम से कम एक-दो बातें तो पाकिस्तान से मनवा लेनी चाहिए थीं। पाकिस्तानी जेल में कैद कुलभूषण जाधव की रिहाई। ५६५ भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी वैष्ठद में सड़ रहे हैं। उनकी तत्काल रिहाई हो।कम से कम इतना तो उपकार मोदी को भारतीय जनता पर करना चाहिए था। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और युद्ध विराम (ट्रंपकृत) स्वीकार करने के बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान से कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ दो। इसे भारत को दे दो।

तमस से ज्योति की ओर एक सुधारवादी यात्रा

यह वह समय था जब हिन्दुस्तान एक तरफ विदेशी दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था वहीं दूसरी तरफ रूढ़िवाद, धार्मिक संकीर्णता, सामाजिक कुरीतियों और दमघोंटू प्रथाओं के बोझ तले दबा हुआ था। तभी एक मसीहा, समाज-सुधारक एवं क्रांतिकारी महामानव अवतरित हुआ जिसने तमाम बुराइयों को चुनौती दी और आखिरी सांस तक बदलाव के लिये क्रांतिकारी योद्धा की तरह लड़ा। ये मसीहा था राजा राममोहन राय। इन्हें देश एवं दुनिया आज भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत के तौर पर याद करती है। अपने दौर में वे भारतीय पुनर्जागरण के पितामह बनकर सच्चे जीवन की लौ बनें और इस लौ का आह्वान था नये भारत का निर्माण। वे तमस से ज्योति की ओर एक बहुआयामी सुधारवादी यात्रा का उजाला थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पश्चिमी विचारों से प्रभावित था, सबसे शुरूआती सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी विचारक के रूप में राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा तथा सामाजिक समानता के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। राय के प्रयासों से ही भारत में आधुनिक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव पड़ी। राय के बाद, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जैसे सुधारकों ने ब्रह्म समाज के विचारों को आगे बढ़ाया और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। उन्नीसवीं सदी के भाल पर अपने कर्तृत्व की जो अमिट रेखाएं उन्होंने खींची, वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। वे साहित्यस्त्रष्टा के साथ-साथ धर्मक्रांति एवं समाजक्रांति के सूत्रधार विराट व्यक्तित्व थे। राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल स्थित हुगली जिले के राधानगर गांव में 22 मई 1772 को

हुआ। पिता रमाकांत राय शुद्ध वैष्णव परंपरा को मानने वाले थे, वहीं माता तारिणी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूरा परिवार कट्टर हिन्दु परंपराओं का हिमायती था लेकिन राममोहन राय को बिना तर्क किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए जब केवल 15 साल के थे तो उन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर सवाल खड़े कर दिये। साथ ही अन्य प्रथाओं की भी आलोचना करनी आरंभ कर दी। हिन्दू परंपराओं का विरोध करना शुद्ध वैष्णव परंपरा को मानने वाले पिता रमाकांत को नागवार गुजरी। पिता-पुत्र में गहरा मतभेद हो गया। राय को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया गया। यहां उन्होंने बांग्ला, पारसी, अरबी, संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहां भी वो हिन्दू परंपराओं और प्रथाओं को तर्क की कसौटी पर परखते रहे और सवाल उठाते रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी कर ली, यहां वे कई अंग्रेजों के संपर्क में आये। उनकी सभ्यता, सोच और तौर-तरीकों को करीब से महसूस किया।

उन्होंने समझ लिया कि पश्चिमी सभ्यता विकास की प्रक्रिया में काफी आगे निकल गयी है जबकि हिन्दुस्तान इसके मुकाबले सदियों पीछे जी रहा है।

राय ने हिन्दू ग्रंथों के साथ इस्लाम एवं ईसाई धर्मों एवं ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्हें एक बात समझ आयी कि हिन्दू धर्म ग्रंथों में वो कतई नहीं लिखा है जो पोंगा पंडित, लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनमानस अपने ग्रंथों की मूलभावना से काफी अनजान है। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्मग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गये थे और लोगों की पहुंच से दूर थे। इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथों का हिन्दी, बांग्ला, अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद किया। उन्होंने अपने अखबारों संवाद कौमुदी और मिरात-उल-अखबार में लेखों के जरिये आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। वे एक महान समाज सुधारक, विचारक एवं क्रांतिपुरुष थे, जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों के लिए अनूठे एवं विलक्षण उपक्रम किये। उन्होंने व्यक्ति-क्रांति के साथ समाज-क्रांति करते हुए सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया।

राय का मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिताएं समाज की स्थिति को सुधारने के बजाय क्षति का कारण, परेशानी का स्त्रोत, सामाजिक जीवन के लिए हानिकारक और लोगों को भ्रमित करने वाली बन गई हैं। उनका यह भी मानना था कि बलिदान और अनुष्ठान लोगों के पापों की भरपाई नहीं कर सकते; यह आत्म-शुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक सुधार से सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों का सूत्रपात किया। राय अपने समय से बहुत आगे चलने एवं सोचने वाले दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के बारे में उनकी समझ ने आधुनिक युग के महत्त्व को बखूबी समझा। ये सिद्धांत वर्तमान न्यू इंडिया के विचार को प्रेरित करते हैं। राय ने वर्ष 1803 में अपनी पहली पुस्तक तुहफत-उल-मुवाहिदीन या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एकल ईश्वर की अवधारणा के पक्ष में तर्क दिया है। उन्होंने अपने इस तर्क में प्राचीन हिंदू ग्रंथों के एकेश्वरवाद का समर्थन करने के लिये वेदों और पाँच उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्तिपूजा, जातिगत रूढ़िवादिता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिये कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। जब उनके बड़े भाई का देहांत हो गया तो परंपरा के मुताबिक गांव वालों ने पंडितों के साथ मिलकर उनकी भाभी को सती हो जाने के लिए मजबूर किया। उन्हें मृतक के साथ उसी चिता में जिंदा जला दिया गया। इस घटना से राय बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी क्रूर प्रथा को धर्म के नाम पर खुलेआम होते देखा। उन्होंने वर्ष 1818 में सती-विरोधी संघर्ष शुरू किया और पवित्र ग्रंथों का हवाला देते हुए यह साबित करने का प्रयास किया कि सभी धर्म मानवता, तर्क और करुणा की बात करते है।

रूसी कोरियोग्राफर यूरी ग्रिगोरोविच का निधन

एजेंसी
मॉस्को। रूसी कोरियोग्राफर यूरी ग्रिगोरोविच का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सहायक अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव ने रूसी संवाद एजेंसी स्पूतनिक को यह जानकारी दी। श्री कोलेसनिकोव ने कहा, डेढ़ घंटे पहले उत्कृष्ट सोवियत और रूसी कोरियोग्राफर यूरी ग्रिगोरोविच का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कोलेसनिकोव ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई की तारीख और जगह की घोषणा अलग से की जाएगी।

उड़ानों की बहाल करने के लिये कई देशों से बात हो रही है : रूस

मॉस्को। रूस की संघीय वायु परिवहन एजेंसी (रोसावियात्सिया) उड़ानों को बहाल करने के संबंध में कई देशों के विमानन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। एजेंसी के प्रमुख दिमित्री याद्रोव ने हेलीरूसिया 2025 फोरम के दौरान संवाददाताओं को यह जानकारी दी। रूसी परिवहन मंत्रालय ने 14 मई को ब्रिक्स के परिवहन मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि रूस ब्रिक्स देशों के साथ हवाई यातायात का विस्तार करने और नये उड़ान मार्ग खोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात के विकास पर विदेश मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और आर्थिक विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त कार्य जारी है। हम कई देशों के विमानन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई देश जिन्होंने उड़ानें निलंबित कर दी हैं, वे उन्हें फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई ऐसे देश हैं, जहां रूसी एयरलाइंस उड़ान भरने के लिए तैयार हैं।

अमेरिका के साथ परमाणु समझौता संभव है : ईरान

तेहरान। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसे भयभीत करने की प्रवृत्ति छोड़ दे तो दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता संभव हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ईरान को 'डराना' बंद कर दे तो ईरान अमेरिका के साथ समझौता कर सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता संभव है, लेकिन इसके लिए एक बुनियादी शर्त आवश्यक है। अमेरिकी पक्ष को अपनी शर्तें थोपना और ईरान को डराना बंद करना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग के आगे नहीं झुकेंगे।

राजा के पक्षधर नेताओं की प्रधानमंत्री को चेतावनी- हेलीकॉप्टर से भागने की तैयारी कर लें

काठमांडू। नेपाल में राजसंस्था की पुनर्बहाली को लेकर 29 मई से शुरू होने जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन से गणतंत्र को समाप्त करने का दावा करते हुए आरपीपी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार का अनिश्चितकालीन आंदोलन देश में राजसंस्था की पुनर्बहाली के बिना नहीं रुकने वाला है। राजशाही पक्षधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि जब जनता सड़कों पर आएगी तो सत्ता पर बैठे लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में शासन पर बैठे लोगों को जनता ने कैसे भगाया, इस बात की याद दिलाते हुए लिंगदेन ने कहा कि हालांकि, हम उस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से भागने का मौका दिया जाएगा। लिंगदेन का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर सरकार ने बल प्रयोग किया तो जनता के आक्रोश को वो संभाल नहीं पाएगी। आरपीपी के नेतृत्व में 29 मई से 40 से अधिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। नेपाल में 29 मई को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आरपीपी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन से ही गणतंत्र को खत्म कर राजसंस्था पुनर्बहाली के लिए संघर्ष की शुरुआत की जा रही है।

नेपाल में वामपंथी दलों के बीच एकता कराने को चीन सक्रिय, पूर्व राष्ट्रपति को मिला बीजिंग दौरे का न्यौता

एजेंसी
काठमांडू। नेपाल में एक बार फिर से प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता की चर्चा और बहस शुरू हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख विपक्षी नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड की पार्टी के बीच एकता कराने की मध्यस्थता के लिए चीन सक्रिय हो गया है। इसी बीच बीजिंग ने देश की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को बीजिंग भ्रमण का न्यौता दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल से सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को 24 मई से एक सप्ताह के चीन भ्रमण पर बीजिंग का न्यौता मिला है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यूएमएल पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ बीजिंग जा रही विद्या भंडारी की वहां कई खास राजनीतिक मुलाकात होना तय है। चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने पूर्व

राष्ट्रपति भंडारी के चीन भ्रमण की पुष्टि की है। काठमांडू आए राजदूत ओली ने बताया कि कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंतरराष्ट्रीय विभाग की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग दौरे के समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात तय है।चीन की पहल पर और पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी के प्रयास से पिछली बार हुई कम्युनिस्ट एकता को सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। बाद में ओली और प्रचंड की व्यक्तिगत टकराव की वजह से वह नहीं हो पाया। चीन एक बार फिर से नेपाल के प्रमुख वामपंथी दलों खास कर ओली और प्रचंड की पार्टी के बीच एकता कराने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी वजह से ओली की पार्टी से सक्रिय राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को चीन बुलाकर एक बार फिर से दोनों प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता कराने के अपने प्रयास में चीन ने भंडारी को बीजिंग बुलाया है।

जापानी कैबिनेट की स्वीकृति दर गिरकर 22 प्रतिशत पर पहुंची

एजेंसी
टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की कैबिनेट की स्वीकृति रेटिंग 22 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। जापानी अखबार मेनिची ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इशिबा की कैबिनेट की स्वीकृति रेटिंग में अप्रैल से 02 प्रतिशत की गिरावट आई है। अप्रैल में स्वीकृति दर 22 प्रतिशत थी। वहीं मार्च में यह 23 प्रतिशत थी। अखबार के अनुसार 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकार में अविश्वास व्यक्त किया है। सैंतालीस प्रतिशत ने 'सरकारी उपायों के लिए आशा की कमी' का हवाला दिया, जबकि 34 प्रतिशत ने श्री इशिबा के 'नेतृत्व कौशल की कमी' को उनके संदेह के कारणों के रूप में इंगित किया। श्री इशिबा के समर्थकों में भी 49 प्रतिशत ने सरकार का समर्थन केवल इसलिए किया, क्योंकि उन्हें 'अन्य उम्मीदवारों या पार्टियों की कमी' दिखाई दी। मेनिची की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 46 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ श्री इशिबा के पदभार संभालने के बाद से जनता का समर्थन लगातार कम होता गया है। यह सर्वेक्षण 17-18 मई को 2,045 प्रतिभागियों के बीच फोन पर किया गया था। क्योडो न्यूज एजेंसी के सर्वेक्षण में शिगेरु इशिबा की सरकार की अनुमोदन रेटिंग 27.4 प्रतिशत के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल से 5.2 अंक कम और मार्च के 27.6 फीसदी से कम है। अविश्वास 55.1 प्रतिशत रहा। योमिउरी अखबार ने 14 अप्रैल को बताया कि उसके अपने सर्वेक्षणों से पता चला है कि सरकार की रेटिंग लगातार तीसरे महीने रिकॉर्ड-निम्न 31 प्रतिशत पर अटकी हुई है। जापान में गर्मियों में उच्च सदन के चुनाव होंगे। सरकार के लिए समर्थन का निम्न स्तर इशिबा की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से छह लोगों की मौत, 14 घायल

एजेंसी
जकार्ता। इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ प्रांत में पांच और लोगों के शव बरामद होने के बाद अचानक आयी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या छह हो गयी है, जबकि 14 लोग अभी भी लापता हैं। प्रांतीय तलाश एवं बचाव कार्यालय के प्रमुख येफ्री सबरुद्दीन ने बताया कि कुछ शव सतह पर पाए गए, जबकि अन्य गुनुंग अरफाक रीजेंसी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लकड़ी और शाखाओं के ढेर के नीचे दबे हुए थे। उन्होंने कहा आज पांच शव मिले हैं। उन्हें एक अस्थायी चौकी पर ले जाया गया है। हमारा ध्यान अब 14 लापता लोगों की तलाश पर है। हम उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे।÷ उन्होंने कहा कि शवों की बरामदगी के बाद तलाश और बचाव अभियान का अगला चरण आपदा स्थल से बहने वाली नदियों के निचले इलाकों में स्थानांतरित हो जाएगा। संभावना है कि पीड़ित नीचे की ओर बह गए होंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण यह अभियान मैन्युअल रूप से चलाया जा रहा है, जिससे भारी मशीनरी का

उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि, क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण खोज को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी अचानक बाढ़ या भूस्खलन का खतरा है, जिससे बचावकर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।मंगलवार को अभियान फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अगर मौसम की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इसमें फिर से देरी हो सकती है। गौरतलब है कि गुरुवार रात भारी बारिश के बाद गुनुंग अरफाक रीजेंसी में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। क्षेत्र में खराब संचार पहुंच के कारण बचाव दलों को आपदा की सूचना देने में देरी हुई।

ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के पानी में फंसे आठ लोगों को बचाया

एजेंसी
सिडनी। आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में फंसे आठ लोगों को बचा लिया गया है।ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग (बीओएम) ने सुबह सिडनी से 100 किलोमीटर दूर प्रांत के पांच क्षेत्रों में तेज बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटों में 180 मिलीमीटर (मिमी) तक बारिश होने के आसार हैं, जिससे अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। सिडनी से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित छोटे से शहर वाइ में पिछले 24 घंटों में आज सुबह तक 120 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गयी है।राज्य आपातकालीन सेवा (एसईएस) ने रविवार को पूरे प्रांत में सहायता के लिए 346 कॉल सुनी गयी और उनका जवाब दिया। इनमें से 272 राज्य के उत्तर के क्षेत्र से आयी थीं। उन्होंने बताया कि आठ लोगों को बाढ़ के पानी में फंसे वाहनों से बचाया गया। उन्होंने बातया कि तक बारिश होने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एंगस हाइन्स ने कहा कि लगातार तीन-चार दिन बारिश होने

सभी आठ बचाव घटनाएं प्रांत में हुईं, जिनमें से एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीओएम ने बताया कि सिडनी में आज करीब 20 मिमी बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार से शुक्रवार के बीच कुल 100 मिमी से उत्तर-पूर्वी प्रांत में बाढ़, सड़क बंद होने और घरों या व्यावसायिक स्थानों में पानी भरने के आसार हैं। वहीं, सिडनी सहित पूर्वी प्रांत के समुद्र तट के 500 किलोमीटर क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है।

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता संरक्षणवाद के खिलाफ उदाहरण स्थापित करेगा : ऑस्ट्रेलियाई मंत्री

एजेंसी
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता अन्य देशों के लिए संरक्षणवाद को अस्वीकार करने के लिए 'एक उदाहरण स्थापित करेगा।' एक वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने यह बात कही। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने 'नाइन एंटरटेनमेंट' अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि वह मंगलवार को अपने यूरोपीय संघ के समकक्ष, व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से बात करेंगे और उन्हें मुक्त व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करेंगे। श्री फैरेल ने कहा, 'यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की स्थिति में हैं, इसलिए यह संदेश जाता है कि संरक्षणवाद आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है।' ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने 2018 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की, इससे पहले कि 2023 में वार्ता टूट जाए, जब दोनों पक्ष ऑस्ट्रेलियाई कृषि निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच पर एक समझौते पर नहीं पहुंच सके।

यदि इजराइल ने ताजा आक्रमण जारी रखा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे -ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा

एजेंसी
लंदन। ब्रिटेन , फ्रांस और कनाडा ने धमकी दी है कि यदि इजरायल गाजा में अपने सैन्य अभियान जारी रखता है और मानवीय सहायता के प्रवेश को रोकता है तो उन पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीएनएन के अनुसार तीनों देशों के नेताओं के एक संयुक्त बयान में कहा गया है, यदि इजरायल ने नए सिरे से सैन्य आक्रमण बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंधों को नहीं हटाया, तो हम जवाब में और ठोस कार्रवाई करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि उन कार्रवाइयों में लक्षित प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। नेतन्याहू ने जवाब में नेताओं पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास के लड़ाकों को बहुत बड़ा इनाम देने और इस तरह के और अत्याचारों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया। एक अलग संयुक्त बयान में, फ्रांस,

जर्मनी, इटली और ब्रिटेन सहित 23 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने इजरायल से तुरंत गाजा में सहायता की ÷पूरी तरह से बहाली की अनुमति देने का आह्वान किया। उन्होंने इजरायल से संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों को जीवन बचाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने में सक्षम बनाने की भी अपील की। जारी बयान में कहा गया, हालांकि हम सीमित सहायता के फिर से शुरू होने

> **नेतन्याहू ने जवाब में नेताओं पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास के लड़ाकों को बहुत बड़ा इनाम देने और इस तरह के और अत्याचारों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया।**

के संकेतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन इजरायल ने दो महीने से अधिक समय तक गाजा में मानवीय सहायता को जाने से रोक दिया है। भोजन, दवाइयां और आवश्यक आपूर्ति समाप्त हो गई है। आबादी भुखमरी का सामना कर रही है। गाजा के लोगों को वह सहायता मिलनी चाहिए जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है।

बांग्लादेश की अभिनेत्री नुसरत फारिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, हत्या के प्रयास के केस में ढाका अदालत ने दी जमानत

एजेंसी
ढाका।बांग्लादेश की मशहूर अभिनेत्री नुसरत फारिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने जेल जाने के 24 घंटे बाद ढाका की अदालत ने आज सुबह जमानत प्रदान कर दी। 31 वर्षीय फारिया को हत्या के प्रयास के एक केस में हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। द डेली स्टार अखबार के अनुसार, फारिया के वकील मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि ढाका की एक अदालत ने आज सुबह अभिनेत्री को जुलाई विद्रोह से जुड़े हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी। वकील हुसैन ने बताया कि ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कल उन्हें इस मामले के सिलसिले में जेल भेज दिया गया। अदालत ने कल जमानत

याचिका पर सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, क्योंकि उनके वकील इफ्तिखार ने उनके यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि वह नौ जुलाई से 13 अगस्त के बीच कनाडा में थीं, जब ढाका के भटारा इलाके में अपराध हुआ था। अभिनेत्री की गिरफ्तारी की कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों, खासकर जुलाई के विद्रोह के दौरान मुखर रहे लोगों ने व्यापक आलोचना की थी। अभिनेत्री को कल सुबह करीब 10:00 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया, इससे एक दिन पहले उन्हें हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया गया था। वह थाईलैंड जा रही थीं। पिछले साल 19 जुलाई को भटारा में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल इनामुल हक ने इस साल 27 मार्च को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, 17 अभिनेता-अभिनेत्री और 265 अन्य के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। 29 अप्रैल को भटारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने अदालत के निर्देशानुसार इस पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उल्लेखनीय है नुसरत फारिया का पूरा नाम नुसरत फारिया मजहर है। वह मॉडलिंग, गायन, टेलीविजन प्रस्तोता और रेडियो जॉकी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर नुसरत फारिया अकसर अपने लुक और पोस्ट की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिलचस्प यह है कि नुसरत को 2023 की फिल्म 'मुजीबः द मेकिंग ऑफ ए नेशन' में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि मिली। यह फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित थी।

कान्स रेड कार्पेट पर शर्मिला टैगोर की सादगी ने जीता दिल

एजेंसी
कान्स। कुछ दिन पहले फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का भव्य आगाज़ हुआ, जिसमें दुनियाभर से कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर भी नजर आईं। रेड कार्पेट पर उनकी सादगी और गरिमा ने सभी का ध्यान खींचा। शर्मिला टैगोर ने ट्रेडिशनल रेशमी साड़ी पहनकर शुद्ध भारतीय अंदाज़ में शिरकत की, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। फैन्स खासतौर पर इस बात से प्रभावित हुए कि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस की बजाय एक साधारण और खूबसूरत साड़ी को प्राथमिकता दी। उनकी यह उपस्थिति भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को ग्लोबल मंच पर बखूबी दर्शा रही थी। कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 के रेड कार्पेट पर भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज अभिनेत्रियों, शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल ने अपनी अद्भुत उपस्थिति से

सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म अरण्येर दिन रात्रि की स्क्रीनिंग के अवसर पर वहां मौजूद थीं। यह फिल्म जाने-माने निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा प्रस्तुत की गई, जो स्वयं सत्यजीत रे के प्रशंसक हैं। शर्मिला टैगोर ने पारंपरिक हरे रंग की साड़ी पहनी थी, उन्होंने अपने लुक को एक सुनहरे क्लच और नाजुक बालियों के साथ पूरा किया। उनकी सादगी और शाही अंदाज़ ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, सिमी गरेवाल सफेद रंग की एक आकर्षक पोशाक में नजर आईं। उन्होंने गुलाबी गाउन के ऊपर एक लंबा कोट पहना हुआ था और एक खूबसूरत हार से अपने लुक को सजाया। रेड कार्पेट पर इन दोनों अभिनेत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति को देख कर प्रशंसकों और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने उनकी खूबसूरती, शालीनता और भारतीय सिनेमा की गरिमा की खूब सराहना की। शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी ने फ्रेंच रिवेरा से अपनी मां के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इन पलों को यादगार बताते हुए कैप्शन में लिखा, कान्स 2025, माँ और मैं... अविस्मरणीय क्षण।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के प्रवासियों की संरक्षित स्थिति को रद्द करने की दी अनुमति

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को हजारों वेनेजुएला प्रवासियों के लिए संरक्षित स्थिति को रद्द करने की अनुमति दी है। जिससे कई लोगों को निर्वासित किया जा सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के एक आपातकालीन अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिससे अधिकारियों को पिछले बाईडेन प्रशासन के एक फैसले को पलटने की अनुमति मिल गई, जिसने लगभग 3लाख 50 हजार वेनेजुएला के लोगों को अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) सुरक्षा प्रदान की थी। टीपीएस अमेरिकी सरकार द्वारा एक पदनाम है जो कुछ देशों के व्यक्तियों को अस्थायी आव्रजन राहत प्रदान करता है, जो असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि चल रहे सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएँ, या अन्य संकट जो नागरिकों के लिए अपने देश में वापस जाना असुरक्षित बनाते हैं। बाईडेन प्रशासन ने वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देते हुए मार्च 2021 में घोषणा की कि वेनेजुएला के लोग टी.पी.एस. के लिए पात्र होंगे, जो 1990 में स्थापित एक संघीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विदेशी व्यक्तियों को मानवीय सहायता प्रदान करना है।

अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति बुकेले की आलोचक वकील लोपेज गिरफ्तार

एजेंसी
सैन सैल्वाडोर। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की मुखर आलोचक और प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इशारे पर की गई गिरफ्तारी की अधिकार समूहों ने तीखी आलोचना की है। समूहों का कहना है कि यह देश में अधिनायकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप जड़ा है। सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, अल साल्वाडोर में अधिकारियों ने राष्ट्रपति नायब बुकेले की आलोचना करने वाली प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज गिरफ्तार किया है। अल साल्वाडोर के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने कहा कि अधिकार संगठन क्रिस्टोसल की भ्रष्टाचार विरोधी और न्याय इकाई की प्रमुख रूथ एलोनोरा लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान की गई जांच और एकत्रित जानकारी के आधार पर की गई। पीड़ित लोपेज की मां और उनके पति ने क्रिस्टोसल के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसे कहां रखा गया है कि यह तक नहीं बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उसके घर पर झूठे बहाने से आए और उसे बाहर निकालने के लिए एक यातायात दुर्घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और वारंट देखने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह अभी भी अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक्स पर पोस्ट किए गए औपचारिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। क्रिस्टोसल में रणनीतिक मुकदमेबाजी के निदेशक अब्राहम एब्रेगो ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार दमन करने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह तक नहीं बताया जा रहा कि वकील और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोपेज को कहां रखा गया है। लोपेज ने बुकेले सरकार की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। अपराध पर नकेल कसने के लिए चल रही आपातकालीन स्थिति के दौरान दमन की निंदा की है। लोपेज को 2024 में बीबीसी ने 100 प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वो 2009 और 2014 के बीच सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष यूजेनियो चिकास की सलाहकार थीं। चिकास को पिछले फरवरी में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बुकेले ने देश में वर्षों से व्याप्त अपराध और गिरोह हिंसा को रोकने के लिए विवादास्पद उपाय लागू किए हैं। 2022 में सांसदों के समर्थन से उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। यह उपाय 30 दिन तक चलने वाला था, लेकिन इसे दर्जनों बार बढ़ाया गया और आज भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार, आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षा बलों ने देश भर में लगभग 87,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय समूहों ने संयुक्त बयान में लोपेज की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि अल साल्वाडोर में आपातकाल का इस्तेमाल न केवल गिरोह से संबंधित हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया है, बल्कि आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए भी किया गया है।

खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत दीव के घोघला बीच पर बीच सॉकर ग्रुप मैचों के साथ हुई

एजेंसी

दीव। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 (केआईबीजी) के पहले संस्करण की शुरुआत दीव के घोघला बीच पर हुई। इस दिन बीच सॉकर मुख्य आकर्षण रहा। अरब सागर की चमकती लहरों के बीच गोवा और राजस्थान ने लड़कों के दिन का पहला मैच खेला। हालांकि, परिणाम एकतरफा रहा। बीच गेम्स में माहिर गोवा ने 13-9 से जीत के साथ अपना विजयी अभियान शुरू किया।गोवा में समुद्र तटों की भरमार है, जबकि राजस्थान में कोई समुद्र तट नहीं है। इसका मतलब है कि गोवा के लोग घर जैसा माहौल महसूस कर रहे थे और राजस्थान के खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आ रहे थे। इससे यह सवाल उठता है कि गैर-तटीय टीमों के लिए केआईबीजी 2025 में मुश्किलें आने वाली हैं? इसका जवाब यह है कि कि यह कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पिछले साल दीव बीच गेम्स में मध्य प्रदेश (जो एक गैर-तटीय राज्य है) ने सबसे ज्यादा पदक जीते। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि गैर तटीय राज्यों के लिए निश्चित रूप से चुनौतियां होंगी। राजस्थान टीम के मैनेजर हरिओम ने केआईबीजी की अगुआई में अपनी टीम के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करी। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए आसान नहीं है। एक गैर-तटीय राज्य के लिए तट पर खेलना हमेशा से मुश्किल रहा है। मेरा मतलब है कि हम राजस्थान में खेल के कृत्रिम मैदान पर अभ्यास करते हैं।

केकेआर ने शिवम शुक्ला और आरसीबी ने मुजरबानी को किया शामिल

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के बाकी बचे मुकाबलों के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपनी-अपनी टीमों में बदलाव किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोवमैन पावेल की जगह शिवम शुक्ला को टीम में शामिल किया है। इसी तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी की जगह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया है। पावेल टॉन्सिल की सर्जरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर शामिल किए गए शिवम शुक्ला लेग स्पिनर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें 30 लाख रुपये में साइन किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी की जगह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया है। एनगिडी 26 मई, 2025 से दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम से जुड़ने के लिए आईपीएल छोड़ेंगे। ऐसे में आरसीबी ने मुजरबानी को 75 लाख रुपये में टीम का हिस्सा बनाया है। ब्लेसिंग मुजरबानी अब तक 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 78 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 12 टेस्ट और 55 वनडे मुकाबलों में भी जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया है। उनके अनुभव को देखते हुए आरसीबी को उम्मीद है कि यह गेंदबाजी विभाग को मजबूती देंगे।

आदिल राशिद ने इंग्लैंड के नए कप्तान के रूप में ब्रूक का किया समर्थन

लंदन। इंग्लैंड के वरिष्ठ स्पिनर आदिल राशिद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली सीरीज से पहले नए कप्तान हैरी ब्रूक का समर्थन किया है। इंग्लैंड के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में एक नया युग शुरू हो रहा है, हैरी ब्रूक 29 मई से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली आगामी एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान पहली बार कप्तानी संभालेंगे। इंग्लैंड की टीम हाल के वर्षों में एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2019 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2022 टी20 विश्व कप की जीत के बाद, हाल ही में सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। आईसीसी टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट आई है, 2023 क्रिकेट विश्व कप में वे सातवें स्थान पर रहे और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वे जीत दर्ज नहीं कर पाए। जोस बटलर के पद छोड़ने के फैसले के बाद, 26 वर्षीय हैरी ब्रूक को इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर खिलाड़ी पूरी तरह से उनके साथ हैं, आदिल राशिद को पूरा भरोसा है कि ब्रूक टीम को आगे ले जाने के लिए सही व्यक्ति हैं।

ड्रीम स्पोर्टस पे अल्टीमेट टेबल टेनिस के साथ की साझेदारी

अहमदाबाद। जमीनी स्तर पर टेबल टेनिस के प्रोत्साहन देने की कवायद के तहत ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन (डीएसएफ) ने अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) के साथ एक विशेष साझेदारी की घोषणा की। यूथ डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में, डीएसएफ ड्रीम यूटीटी जूनियर्स का उद्घाटन करेगा। यह एक अंडर-15 टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे उभरती हुई टेबल टेनिस प्रतिभाओं को पेशेवर लीग का अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ड्रीम यूटीटी जूनियर्स का उद्घाटन 29 मई से 8 जून तक अहमदाबाद में अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग के छठे संस्करण के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे फैनकोड पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। साझेदारी पर बात करते हुए ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ और सह-संस्थापक हर्ष जैन ने कहा, ड्रीम स्पोर्ट्स में, हम 'खेलों को बेहतर बनाने' के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित हैं।

आईपीएल 2025: सम्मान के लिए भिड़ेंगे सीएसके और राजस्थान रॉयल्स

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कब की खत्म हो चुकी हैं। दोनों ही टीमें अब केवल सम्मान के लिए इस मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने के उतरेंगी। इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही होगा–कौन बच पाएगा इस सीजन की सबसे निचली पायदान यानी 'वुडन स्पून' से? सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के सीजन की कहानी एक जैसी खत्म हुई, लेकिन रास्ते काफी अलग रहे। राजस्थान रॉयल्स ने चार ऐसे मुकाबले गंवाए जो उनकी मुट्ठी में थे, वहीं चेन्नई की टीम अपने गौरवशाली इतिहास की परछाई बनकर रह गई। यह फ्रेंचाइज़ी का शायद अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा है।

जहां टीम के स्तर पर अब कोई बड़ी प्रेरणा नहीं बची है, वहीं व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिहाज से यह मुकाबला कई खिलाड़ियों के लिए अहम साबित हो सकता है। युवा खिलाड़ियों और बाहर बैठे सितारों को खुद को साबित करने का एक और मौका मिलेगा, जो इस 'डेड-रबर' मुकाबले को देखने लायक बना सकता है। पिछले मुकाबले में इसी मैदान पर गुजरात टाइटंस ने आसानी से 200 का लक्ष्य हासिल किया था। हालांकि पिच में बदलाव संभव है, लेकिन आमतौर पर यहां आक्रामक बल्लेबाजी को मदद मिलती है। हेड टू हेड की बात करें तो सीएसके का राजस्थान पर अब तक 16-14 का बढ़त है, लेकिन साल 2020 के बाद से राजस्थान ने चेन्नई के खिलाफ 9 में से 7 मैच जीते हैं। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, चेन्नई के स्पिन जोड़ी अश्विन-जडेजा के खिलाफ ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाए हैं। छोटे मैदान के बावजूद यह जोड़ी उन्हें परेशान कर सकती है।

ब्राजील के पूर्व मिडफील्डर रेनेटो ऑगस्टो ने फ्लुमिनेंस क्लब को कहा अलविदा

एजेंसी

रियो डी जेनेरियो। ब्राजील के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर रेनेटो ऑगस्टो ने रियो डी जेनेरियो स्थित फुटबॉल क्लब फ्लुमिनेंस से आपसी सहमति के आधार पर अपना नाता तोड़ लिया है। क्लब ने एक संक्षिप्त सोशल मीडिया बयान में यह जानकारी दी। फ्लुमिनेंस क्लब ने 37 वर्षीय खिलाड़ी के जाने के पीछे किसी कारण का उल्लेख नहीं किया। क्लब ने अपने बयान में कहा, फ्लुमिनेंस खिलाड़ी द्वारा दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद करता है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। रेनेटो ऑगस्टो ने जनवरी 2024 में कोरिंथियंस से फ्लुमिनेंस में शामिल होकर सभी प्रतियोगिताओं में कुल 36 मैच खेले। उनका अनुबंध दिसंबर 2024 तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही क्लब को छोड़ दिया। 20 साल के अपने पेशेवर करियर में रेनेटो ने फ्लेमेंगो, जर्मन क्लब बायर लेवरकुसेन और चीनी क्लब बीजिंग

गुओआन के लिए भी खेला है। वे ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए 33 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 2018 फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की उस टीम का हिस्सा रहे जो क्वार्टरफाइनल तक पहुँची थी। रेनेटो के इस फैसले के बाद फुटबॉल जगत में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं।

आईपीएल 2025 से बाहर होने पर, एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत बोले- खकई गैप थे जिन्हें भरना मुश्किल हो गया'

एजेंसी

लखनऊ। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का सफर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया जब सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने उन्हें हराकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। मुकाबले के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बात की और बताया कि चोटिल खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी ने टीम को काफी नुकसान पहुँचाया। पंत ने कहा, यह हमारे लिए सबसे अच्छा सीजन नहीं रहा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमें अंदाज़ा था कि चोटों के कारण कई गैप हैं। हमने सोचा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इन गैप्स को भरना मुश्किल होता चला गया। एलएसजी के लिए तेज़ गेंदबाज़ी विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। मोहसिन खान पूरे सीजन से बाहर रहे, जबकि तेज़ गेंदबाज़ मयंक यादव, जिन पर टीम ने काफी भरोसा जताया था, ज्यादातर समय चोटिल रहे। मयंक की वापसी भी लंबी नहीं चल सकी और वह दोबारा कमर की चोट से जूझते नज़र आए। इसके अलावा अवेश खान और आकाश दीप भी फिटनेस समस्याओं से जूझते रहे और सीजन के बीच में ही टीम से जुड़ सके।ऋषभ पंत ने आगे कहा, हमने जिस तरह से नीलामी की

योजना बनाई थी, अगर वही गेंदबाज़ी अटैक होता तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन यही क्रिकेट है, कभी चीजें आपके पक्ष में जाती हैं, तो कभी नहीं। हमें उन सकारात्मक बातों पर फोकस करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। एलएसजी की बल्लेबाज़ी में इस सीजन दम ज़रूर दिखा। मिशेल मार्श और एडेन मार्करम की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम ने 205 रन बनाए, हालांकि पंत के मुताबिक यह स्कोर कम से कम 10 रन कम था। एसआरएच ने यह लक्ष्य सिर्फ 10 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। बावजूद इसके, कुछ सकारात्मक पहलू भी एलएसजी के लिए रहे। युवा लेग स्पिनर दिग्वेश राठी ने अपने डेब्यू सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। 25 वर्षीय गेंदबाज़ ने 12 मैचों में 14 विकेट झटके और उनकी इकॉनमी 8.08 रही। भी उन्होंने 2 विकेट लिए और सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहे। पंत ने कहा, राठी ने जिस तरह से गेंदबाज़ी की, वह देखने में बहुत अच्छा रहा। वह हमारे लिए इस सीजन की सबसे बड़ी सकारात्मक चीज़ों में से एक रहे। सीजन के दो हिस्सों का अंतर बताते हुए पंत ने कहा, शुरुआत में हमने चीजों को संभाला, खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, अच्छे प्रदर्शन कर रही टीमों के खिलाफ पकड़ बनाना मुश्किल होता गया। एलएसजी भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हो, लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन और खिलाड़ियों की वापसी भविष्य के लिए टीम को उम्मीद जरूर देंगे।

आईपीएल 2025: प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई एलएसजी, चौथे स्थान के लिए मुंबई और दिल्ली में मुकाबला

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के प्लेऑफ की दौड़ से एक और टीम बाहर हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पांचवीं टीम बन गई है। अब तीन टीमें - गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स - ने पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चौथे और अंतिम स्थान के लिए अब मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच - मुंबई इंडियंस (एमआई) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच है।

21 मई को होगा निर्णायक मुकाबला

आईपीएल के फिर से शुरू होने के बाद मुंबई इंडियंस का यह पहला मुकाबला होगा, जो 21 मई को वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच प्लेऑफ की तस्वीर काफी हद तक साफ कर सकता है। अगर मुंबई यह मैच जीतती है, तो उसके 16 अंक हो जाएंगे और वह सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, भले ही उसका आखिरी लीग मैच पंजाब किंग्स के

खिलाफ बाकी हो। वहीं, दिल्ली अधिकतम 15 अंक तक ही पहुंच सकती है, इसलिए वह बाहर हो जाएगी।

अगर दिल्ली ने मुंबई को हराया तो समीकरण बदलेंगे

अगर दिल्ली कैपिटल्स यह मैच जीत जाती है, तो उसके 15 अंक हो जाएंगे और मुंबई 14 पर ही रह जाएगी। ऐसे में दोनों टीमों के पास प्लेऑफ में पहुंचने का एक और मौका होगा, जो उनके अंतिम लीग मुकाबलों पर निर्भर करेगा। दिल्ली अगर अपने दोनों मैच जीतती है (मुंबई और पंजाब के खिलाफ), तो उसके 17 अंक हो जाएंगे और वह सीधे प्लेऑफ में पहुंचेगी। मुंबई अगर दिल्ली से हारने के बाद पंजाब को हराती है, तो उसके 16 अंक होंगे। यदि दिल्ली पंजाब से हार जाती है, तो वह 15 अंक पर रह जाएगी और बाहर हो जाएगी।

21 मई या 26 मई तक हो सकता है फैसला

चौथे प्लेऑफ स्पॉट की तस्वीर 21 मई को ही साफ हो सकती है, अगर मुंबई जीत जाती है। लेकिन अगर दिल्ली जीतती है, तो यह फैसला 26 मई तक खिंच सकता है, जब मुंबई और पंजाब के बीच आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि प्लेऑफ में पहुंचने की रेस जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन शीर्ष दो स्थानों की लड़ाई, जिससे फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलते हैं, वह लीग के अंतिम चरण तक जारी रहने की संभावना है।

आईपीएल 2025: हैदराबाद ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया, प्लेऑफ से बाहर हुई लखनऊ सुपर जायंट्स

एजेंसी

लखनऊ। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) के अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को छह विकेट से हरा दिया और उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। इस तरह ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पांचवीं टीम बन गई। खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 205 रन बनाए। लखनऊ की ओर से ओपनर मिशेल मार्श और एडन मारक्रम के बीच 115 रन की साझेदारी हुई। मार्श 65 रन और मारक्रम 61 रन बनाकर आउट हुए।इसके बाद निकोलस पूरन ने 45

की पारी खेली। इनके अलावा कोई बल्लेबाजी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। हैदराबाद के लिए ईशान मलिंगा ने दो विकेट चटकाए, जबकि हर्ष दुबे, हर्षल पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक सफलता मिली। 206 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत झटके के साथ हुई। सलामी बल्लेबाज अथर्व ताइडे 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 82 रनों की साझेदारी हुई। अभिषेक 20 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें दिग्वेश राठी ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच कराया। इसके बाद ईशान किशन को हेनरिक क्लासेन का साथ मिला। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 41 रन जोड़े। किशन 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्लासेन 47 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे।

वहीं, कामिंदु मेंडिस 32 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। उन्हें हैमस्ट्रिंग से जूझते देखा गया। अनिकेत वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी पांच-पांच रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ के लिए दिग्वेश राठी ने दो विकेट लिए जबकि विलियम ओरुर्के और शार्दुल ठाकुर को एक-एक सफलता मिली।

अंडर-19 क्रिकेट टीम में देश का प्रतिनिधित्व करेगा कनिष्क चौहान

एजेंसी

सिरसा। सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव डॉ. वेद बेनीवाल ने बताया कि सिरसा का युवा क्रिकेटर कनिष्क चौहान अंडर-19 क्रिकेट टीम में इंग्लेंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। डा. वेद बैनीवाल सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले शाह सतनाम जी क्रिकेट अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिरसा का यह उभरता सितारा क्रिकेट के प्रति अपने समर्पण और सामर्थ्य से भारत की अंडर-19 क्रिकेट का हिस्सा बना है जो न केवल सिरसा बल्कि समूचे हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। डॉ. बेनीवाल ने इस मौके पर हाल ही में अंडर-19 की विजेता बनी सिरसा की टीम और अंडर-23 की फाइनल तक पहुंची क्रिकेट टीम को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि वे हर खिलाड़ी को एक बड़ा मंच देने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते वह मैदान पर परफॉरमेंस दे। उनके जीवन में सिफारिश नाम के शब्द की कोई जगह नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण भारत की टीम में हरियाणा के ख्यातिप्राप्त स्पिनर युजवेंद्र चहल है। डॉ. वेद बेनीवाल ने कहा कि वे अनुभव से कहते हैं कि कनिष्क चौहान में क्रिकेट की जो भूख है, उसी के चलते वह एक दिन सीनियर भारतीय क्रिकेट में भी अपना स्थान बनाएंगे। इससे पूर्व चयनकर्ता हितेश ने अपने संबोधन में खिलाडिों को प्रेरित करते हुए कहा कि क्रिकेटर्स को उनका असली मंच वे खुद अपनी प्रतिभा से दे सकते हैं।

हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू

एजेंसी

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने आज बहुप्रतीक्षित हीरो हॉकी इंडिया लीग (हीरो एचआईएल) 2026 के लिए खिलाड़ी पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की। पंजीकरण प्रक्रिया 19 मई 2025 को शाम 5 बजे से शुरू होकर 20 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक चलेगी। 2024–25 के पुनः आरंभ सत्र की शानदार सफलता के बाद आगामी संस्करण और भी भव्य और प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। पिछली बार 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइज़ियों ने इसमें भाग लिया था।

इसके तहत पुरुष खिलाड़ी के तौर पर पंजिकरण के लिए भारत के अलावा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के देश पात्र हैं। जबकि महिला खिलाड़ियों के लिए भारत के

साथ नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, बेल्जियम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, चिली, जापान, अमेरिका और स्कॉटलैंड देश पात्र हैं। हॉकी इंडिया की ओर से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए शुरू किए गए पंजिकरण लिंक जारी किया गया, जो https://forms.gle/xrVoZdRXoozf~SHS{ है। पिछले सीज़न में 1,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जो लीग की वैश्विक लोकप्रियता और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए मंच की भूमिका को दर्शाता है। हॉकी इंडिया एवं हीरो एचआईएल संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ दिलीप टिर्की ने कहा, हीरो हॉकी इंडिया लीग भारतीय हॉकी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। खिलाड़ियों और दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया ने हमें प्रेरित किया है कि हम 2026 संस्करण को और अधिक भव्य बनाएं। यह लीग न केवल भारत में हॉकी का स्तर ऊंचा कर रही है, बल्कि अंतराष्ट्रीय सहयोग को भी सशक्त बना रही है। हॉकी इंडिया के महासचिव एवं संचालन समिति सदस्य भोला नाथ सिंह ने कहा, पुरुष और महिला दोनों लीगों की सफलता से खेल में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। हम भारत और विदेश के सभी योग्य खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और आगामी ऐतिहासिक सत्र का हिस्सा बनें।

जेकब फर्नले जिनेवा ओपन के दूसरे दौर में

जिनेवा। ब्रिटेन के दूसरे नंबर के खिलाड़ी जैकब फर्नले ने डुसन लाजोविक को हराकर जिनेवा ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया23 वर्षीय खिलाड़ी ने सर्बिया के वाइल्डकार्ड लाजोविक को 6-4, 6-1 से हराकर टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बन गए।

स्कॉटिश खिलाड़ी का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन से होगा।फर्नले ने अप्रैल में मैड्रिड ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने के बाद विश्व में अपने करियर की सर्वोच्च 54वीं रैंकिंग हासिल की, उन्होंने उसी महीने की शुरुआत में बार्सिलोना में क्ले पर अपना पहला पेशेवर मैच खेला था। फ्रेंच ओपन (वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम) रविवार से शुरू हो रहा है।

प्लेऑफ में पंजाब किंग्स: कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम भावना और परस्पर सहयोग को दिया सफलता का श्रेय

एजेंसी

नई दिल्ली। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर आखिरकार 11 वर्षों बाद आईपीएल प्लेऑफ में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक क्षण के बाद, कप्तान श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम में टीम के सामूहिक प्रयास और एक-दूसरे के लिए चिंता करने की भावना को जीत का मूल मंत्र बताया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयश अय्यर ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जब किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता, तब यह कितना मुश्किल होता है। लेकिन आज हमने देखा कि जो खिलाड़ी बाहर बैठे थे, उन्होंने भी मैदान पर जाकर बाकी साथियों की मदद की। यह दर्शाता है कि हर कोई टीम के लिए कितना समर्पित है। अय्यर ने हेड कोच रिकी पोंटिंग का उल्लेख करते हुए कहा, रिकी ने टीम के भीतर 'एक-दूसरे की परवाह' की बात की थी, और आज मैं वह भावना हर खिलाड़ी में देख सका। यही असली टीम भावना है। श्रेयस ने जीत के बाद सभी खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, प्लेऑफ में पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए टीम के हर सदस्य को बधाई। चाहे मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी हों या बेंच पर बैठे साथी, हर किसी ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने टीम से आग्रह किया कि इस ऊर्जा और जोश को आगामी मुकाबलों में भी बनाए रखें, ताकि पंजाब किंग्स इस बार खिताब की दौड़ में और आगे बढ़ सके। पंजाब किंग्स की 11 साल

के बाद प्लेऑफ में वापसी 2014 के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा रही है। लंबे समय से टीम पर प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन इस सीजन में खिलाड़ियों की एकजुटता, नेतृत्व और मेहनत ने टीम को नई दिशा दी।

खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक बना खेलो इंडिया बीच गेम्स: प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी

दीव। भारत के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स (केआईबीजी) का भव्य शुभारंभ दीव के घोघला बीच पर हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आयोजन भारत के खेल कैलेंडर में उत्साह की नई लहर पैदा करेगा और तटीय क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच देगा।

प्रधानमंत्री ने आयोजन स्थल दीव को उचित चुनाव बताते हुए कहा, सूरज, रेत और समुद्र का संगम इन खेलों को न केवल रोमांचक बनाता है, बल्कि यह हमारी समृद्ध विरासत का भी उत्सव है। जैसे-जैसे लहरें तटों से टकरा रही हैं, भारत खेलों के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति राष्ट्रीय गौरव, एकता और युवाओं की आकांक्षाओं को पोषित करती है। खेलो इंडिया बीच गेम्स इसी शक्ति के प्रतीक बनकर उभरे हैं। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने किया। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया बीच गेम्स न केवल एक खेल आयोजन है, बल्कि भारत की पहली बीच स्पोर्ट्स क्रांति का आरंभ है। इस आयोजन में 1350 से अधिक एथलीट अपनी प्रतिभा का मंचन करेंगे। जबकि

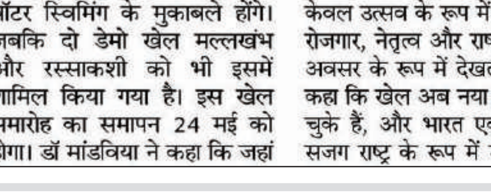

30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभागी इसमें प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। इस दौरान छह प्रमुख प्रतिस्पर्धी खेल- बीच सॉकर, वॉलीबॉल, सेपक टकरॉ, कबड्डी, पेन्चक सिलाट और ओपन वॉटर स्विमिंग के मुकाबले होंगे। जबकि दो डेमो खेल मल्लखंभ और रस्साकशी को भी इसमें शामिल किया गया है। इस खेल समारोह का समापन 24 मई को होगा। डॉ मांडविया ने कहा कि जहां लहरें हों वहां जुनून और जहां रेत हो वहां उत्साह की चिंगारी होनी चाहिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स ने यह चिंगारी जलाई है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार खेलों को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के अवसर के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि खेल अब नया सामान्य बन चुके हैं, और भारत एक फिटनेस-सजग राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इस उद्घाटन समारोह में देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक देने वाले पारंपरिक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां भी हुईं। आयोजन में शामिल गणमान्य अतिथियों में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव व लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

पहले पहना 1300 करोड़ का ताज, अब फटी हुई ड्रेस में कान्स के रेड कार्पेट पर दिखीं

उर्वशी रौतेला

कान फिल्म फेस्टिवल में कई सारे सितारे शामिल हुए हैं, जिनको लेकर काफी चर्चा की जा रही है. हालांकि, कुछ वक्त पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने लुक को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही थीं. हालांकि, इक बार फिर एक्ट्रेस अपनी कान फिल्म फेस्टिवल की ड्रेस को लेकर खबरों में बन गई हैं, ये इसलिए क्योंकि एक्ट्रेस के साथ उप्स मोमेंट हो गया है. दरअसल, उर्वशी ने रेड कार्पेट पर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि साइड से फटी दिख रही है.

कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी पहले पैरेट लुक में दिखी थीं, उन्होंने साथ में तोते जैसा ही एक क्लच भी लिया हुआ था. हालांकि, उनके पहले लुक को लेकर लोगों ने उन पर तरह-तरह की टिप्पणियां की. लेकिन, जब एक्ट्रेस दोबारा रेड कार्पेट पर नजर आईं, तो इस दौरान उन्होंने ब्लैक कलर का प्लेन सा गाउन पहना हुआ था पर दोबारा से लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस ने जो ड्रेस पहनी है वो फटी हुई है.

जानबूझकर किया है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उर्वशी का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनकी ड्रेस के छेड को आराम से देखा जा सकता है. हालांकि, लोगों ने इसको लेकर भी उर्वशी का मजाक ही बनाया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि लग रहा है कि जानबूझकर किया है, ताकि हेडलाइन्स में आ सके. तो वहीं दूसरे ने लिखा है कि वॉर्डरोब मैलफंक्शन है या ड्रेस का फिट इतना खराब था कि ड्रेस ही फट गई.

कॉन्फिडेंस की तारीफ

हालांकि, अगर केवल लुक की बाच करें, तो एक्ट्रेस ब्लैक कलर की इस ड्रेस में काफी एलिगेंट लग रही हैं. फटी ड्रेस में पोज देने के लिए कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की भी तारीफ की है.हालांकि, उर्वशी ऐसे विवादित बयान देती हैं, कि लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं. ड्रेस की बात करें, तो एक्ट्रेस के ब्लैक गाउन को फेमस डिजाइनर नाजा सादे ने बनाया है. एक्ट्रेस ने इस ड्रेस में फोटो भी शेयर किया है.

माधुरी के साथ जब ऋषि कपूर को पहनना पड़ा था बुर्का, एक गलती से पड़ गए लेने के देने

हिंदी सिनेमा में बड़े पर्दे पर कई जोड़ियों ने दर्शकों का दिल हर बार जीता. 90 के दशक में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी काफी पॉपुलर थी. माधुरी और ऋषि ने साथ में स्क्रीन शेयर किया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था. साथ काम करने के दौरान माधुरी और ऋषि का एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया था. एक बार तो जब दोनों हैदराबाद किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे तो फैंस से बचने के लिए माधुरी के साथ ही ऋषि कपूर ने भी बुर्का पहन लिया था. लेकिन ये दांव दोनों कलाकारों पर उल्टा पड़ गया था और पुणे रेलवे स्टेशन पर दोनों पकड़े गए थे.

ऋषि ने शेयर किया था किस्सा

ऋषि कपूर ने साल 2018 में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये किस्सा खुद शेयर किया था. पहले उन्हें माधुरी दीक्षित ने बर्थडे विश किया था. जिस पर ऋषि ने जवाब देते हुए मजेदार किस्सा सुना दिया था. माधुरी ने ऋषि को विश करते हुए लिखा था, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपका दिन अच्छा हो और आने वाला साल भी.

ऋषि कपूर ने माधुरी से मिली शुभकामनाओं पर लिखा था, धन्यवाद माधुरी. मुझे एक मजेदार घटना याद आ रही है हम दोनों ने हैदराबाद (याराना की शूटिंग) में 'बुर्का' पहना था (ताकि कोई हमें पहचान न सके) और भीड़ भरे पुणे स्टेशन पर मेरा 'बुर्का उतर गया. उसके बाद सफर नर्क जैसा हो गया. सीक्रेट रखने के लिए इतना कुछ करना पड़ा.

माधुरी-ऋषि ने इन फिल्मों में साथ किया काम

ऋषि कपूर ने साल 1973 में आई सुपरहिट फिल्म 'बॉबी' से अपने करियर की बतौर लीड एक्टर शुरुआत की थी. वहीं माधुरी ने हिंदी सिनेमा में अपना आगाज साल 1984 की फिल्म 'अबोध' से किया था.

माधुरी और ऋषि दोनों ही फिल्मी दुनिया में बड़ी और खास पहचान बनाने में कामयाब रहे. एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले दोनों दिग्गजों ने साथ में भी काम किया. ऋषि और माधुरी बड़े पर्दे पर 'साहिबान', 'याराना' और 'प्रेम ग्रंथ' जैसी फल्मों में नजर आए. बता दें कि ऋषि अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका साल 2020 में कैंसर से निधन हो गया था.

21 की उम्र में 2 बेटियों की मां बनीं रवीना टंडन को मिलते थे ताने, शादी से पहले पति के सामने रख दी थी ये शर्त

बॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं में शामिल रवीना टंडन ने अपनी फिल्मों के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियां बटोरी. रवीना टंडन का अफेयर अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स संग सुर्खियों में रहा. लेकिन किसी के साथ भी उनका रिश्ता टिक नहीं पाया. इसके बाद उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की. हालांकि शादी से पहले रवीना ने अनिल के सामने एक शर्त रख दी थी. आइए जानते हैं कि आखिर किस शर्त पर एक्ट्रेस अनिल थडानी की दुल्हन बनी थीं ?

शादी से पहले ही बन गईं थीं दो बेटियों की मां

रवीना टंडन का जन्म दिवंगत प्रोड्यूसर रवि टंडन के घर 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में हुआ था. पिता के प्रोड्यूसर होने के चलते रवीना ने भी फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाया. उन्होंने अपनी शुरुआत फिल्म 'पत्थर के फूल' के जरिए की थी. वहीं करियर के शुरुआती दिनों में ही रवीना बिना शादी के दो बेटियों की मां बन गईं थीं. रवीना ने महज 21 साल की उम्र में दो बेटियों छाया और पूजा को गोद लिया था. इसके बाद अनिल थडानी से शादी रचाई थी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी.

इस शर्त पर अनिल की दुल्हन बनी थीं रवीना

रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शदी से पहले कम उम्र में ही मां बनने पर लोग उन्हें ताने सुनाते थे. एक्ट्रेस की शर्त थी कि जो भी उनकी लाइफ में आएगा और उनसे शादी करेगा उसे उनके साथ ही उनकी दोनों बेटियों को भी अपनाना होगा. उन्होंने कहा था मैं पैकेज के साथ आऊंगी. मेरे साथ मेरी बेटियों, डॉगी, मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना होगा. ये शर्त रवीना ने अनिल के सामने भी रखी थी, जिसे अनिल ने स्वीकार किया था. इसके बाद साल 2004 में अनिल और रवीना ने धूमधाम से शादी रचा ली. अब दोनों की शादी को 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है.

दो बच्चों के पैरेंट्स हैं अनिल-रवीना

अनिल थडानी और रवीना टंडन शादी के बाद दो बच्चो के पैरेंट्स बने. कपल का एक बेटा और एक बेटी हैं. बेटे का नाम रणबीर थडानी जबकि बेटी का नाम राशा थडानी हैं. राशा भी मां की राह पर चलते हुए एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होंने इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'आजाद' से डेब्यू किया है.

दुबई के होटल में

मोनालिसा

ने दिखाईं अदाएं, दिए एक से बढ़कर एक पोज, वीडियो दिल जीत लेगा

सोलो ट्रिप करने का क्रेज अब आम लोगों से सेलिब्रिटीज के अंदर भी आ गया है. इसलिए तो मोनालिसा बिना किसी दोस्त या अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के ही दुबई पहुंच गई. वहां से मोनालिसा अपने पल-पल की अपडेट्स फैंस के लिए शेयर कर रही हैं और इस बार तो उन्होंने दुबई के होटल रूम से कुछ तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया है.लगभग 3 दिन पहले मोनालिसा दुबई आई हैं और उन्होंने घर से दुबई और दुबई से घर तक की चीजों को शेयर करने के बारे में अपने एक पोस्ट में बताया था. फिलहाल वो दुबई में ही हैं और अकेले ही होटल में एन्जॉय करने के पोस्ट फैंस के लिए शेयर किए हैं.

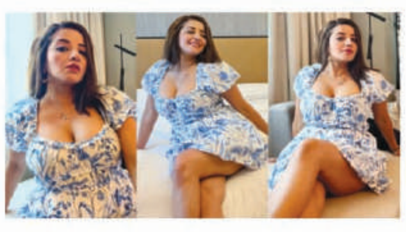

मोनालिसा ने दुबई के होटल रूम में किया डांस

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आज ही यानी 19 मई को शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, उफ्फ्फ ये गाना.' इसके साथ उन्होंने 90'ह्य रील और लव दिस सॉन्ग हैशटैग लिखते हुए हार्ट इमोजी शेयर किया है.मोनालिसा ने इस वीडियो में जो गाना लगाया है वो 1995 में आई फिल्म टक्कर का है, जिसका नाम 'आंखों में बसे हो तुम' है. इस गाने को अलका यागनिक और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया था, जबकि इसे सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे पर फिल्माया गया था. मोनालिसा के इस वीडियो पर ज्यादातर फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर किया है.

तस्वीरों में भी कमाल लग रही हैं मोनालिसा

इस वीडियो से पहले यानी 18 मई को मोनालिसा ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयरे की थीं, जो उनके होटल रूम की ही थीं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 'अगर किसेस स्टार्स होते, तो मैं तुम्हें आसमान दे देती.' इस पोस्ट के साथ भी उन्होंने हार्ट इमोजी शेयर की है.

वीडियो और फोटोज में मोनालिसा ने एक ही वन पीस ड्रेस पहनी है जो व्हाइट और स्काई ब्लू कलर की है.

इन तस्वीरों में मोनालिसा ने अलग-अलग पोज दिए हैं और इनमें मोनालिसा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर प्रशांत निशांत ने तीन हार्ट इमोजी कमेंट की है.

वहीं फॉलोवर्स भी इस तस्वीर को हार्ट इमोजी के साथ बता रहे हैं कि उन्हें मोनालिसा के पोस्ट पसंद आ रहे हैं.

सीमा पार करते 184 विदेशी किए गिरफ्तार

केंद्रीय गृह सचिव ने एसएसबी मुख्यालय में की उच्च स्तरीय समीक्षा

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एसएसबी के प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में एसएसबी की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एसएसबी के महानिदेशक ने बताया कि पिछले चार साल में बल ने सीमा पार कर भारत में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे 184 विदेशी गिरफ्तार किए, वहीं 27 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। बैठक में एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने संगठन की वर्तमान संरचना, सीमावर्ती तैनाती, प्रचालन उपलब्धियों, तकनीकी उन्नति और भविष्य की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से भारत-नेपाल एवं भारत-भूटान सीमाओं पर एसएसबी की प्रभावशाली उपस्थिति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं जम्मू-कश्मीर में बल की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। महानिदेशक प्रसाद ने एसएसबी की उपलब्धियां साझा करते हुए

बताया कि 2020 से 2025 के दौरान एसएसबी ने 184 विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से सीमा पार करने पर गिरफ्तार किया। इसी अवधि में 1250 मानव तस्करी के मामलों में 2156 पीड़ितों को मुक्त कराया गया और 1094 तस्करों को पकड़ा गया।एसएसबी ने नक्सल और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में 426 उग्रवादियों को आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के लिए बाध्य किया और 27 उग्रवादियों को मुठभेड़ों में ढेर किया।

प्रसाद ने बताया कि एसएसबी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण प्रयास शामिल हैं। बैठक में इसके अलावा बल के कर्मियों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए एंटी ओबेसिटी ड्राइव और श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आवासीय सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार के तहत वर्ष 2020-21 में 20.40 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 31.95 प्रतिशत आवास संतुष्टि दर्ज की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार, सचिव (बीएम), मृत्युंजय कुमार नारायण, अतिरिक्त सचिव (पी-क्क), संजीव कुमार जिंदल, अतिरिक्त सचिव (पीएम), पौसुमी बासु, संयुक्त सचिव (बीएम), जूही वर्मा, निदेशक, दीपक कुमार, निदेशक (पीएफ) तथा शशांक मणि त्रिपाठी, (ओएसडी) उपस्थित रहे। सशस्त्र सीमा बल की ओर से अपर महानिदेशक डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा, महानिरीक्षक (कार्मिक एवं संचार) गणेश कुमार, महानिरीक्षक (प्रशासन एवं प्रशिक्षण) सोमित जोशी, महानिरीक्षक (प्रचालन एवं आसूचना) वंदन सक्सेना, महानिरीक्षक (प्रावधान) पारुल कुश जैन, महानिरीक्षक (चिकित्सा) डॉ. अशोक राय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बल के जवान उपस्थित रहे।

केंद्र ने बिजली उपकरणों पर गुणवत्ता आदेश लागू करने की समय-सीमा मार्च तक बढ़ाई

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ बिजली उपकरणों पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करने की समय-सीमा को एक साल बढ़ाकर मार्च कर दी है। क्यूसीओ घरेलू तथा वाणिज्यिक सहित ज्यादातर बिजली उपकरणों पर लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने घरेलू, वाणिज्यिक एवं समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए उक्त क्यूसीओ अब 19 मार्च, 2026 से लागू होगा। डीपीआईआईटी ने कहा कि यह निर्णय 15 मई, 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। बैठक में घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपकरणों की सुरक्षा को लेकर 15 मई को हितधारक परामर्श बैठक में चर्चा की गई थी। इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग की चिंताओं को स्वीकार किया और क्यूसीओ को लागू करने की समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमति जताई थी।

तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों से डेयरी क्षेत्र में आएगी क्रांति : शाह

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सहकारी डेयरी क्षेत्र में तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सक्युलैरिटी विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तीन नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। पहली समिति पशु आहार निर्माण, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गभाधान। दूसरी समिति गोबर प्रबंधन मॉडल विकसित करने और तीसरी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्क्युलर उपयोग को बढ़ावा देने पर काम करेंगी। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है और सहकारी डेयरी क्षेत्र इसका एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि डेयरी सहकारी समितियां भारतीय दुग्ध क्षेत्र में दूध उत्पादन और विपणन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं। शाह ने कहा कि वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि डेयरी क्षेत्र को अधिक सतत और पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों की भूमिका डेयरी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है।

ये समितियां छोटे किसानों को स्थिर बाजार, ऋण सुविधा, पशु चिकित्सा और प्रजनन जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में सहकारी डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सक्युलैरिटी को बढ़ावा देने के लिए नए मॉडल विकसित करना और सहकारी समितियों को मजबूत करना शामिल है। अमित शाह ने कहा कि सहकारी डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि डेयरी क्षेत्र को भी मजबूत किया जा सकेगा।

नेहा सिंह राठौर की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुई शिकायत

वाराणसी
बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के खिलाफ हनुमान सेना ने लंका थाने में दी तहरीर। अध्यक्ष सुधीर सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र को ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि नेहा राठौर के अनर्गल वक्तव्य से देश के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। नेहा के वीडियो पाकिस्तान की मीडिया और टेलीविजन पर लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे लोगों में काफी आक्रोश है ।

बालाघाट जिले में पुलिस-नक्सलियों के बीच मुठभेड़

भोपाल
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलालकसा जंगल में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान नक्सली घने जंगल का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके ठिकाने से भारी मात्रा में दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। नक्सलियों की तलाश में पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार, लांजी थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी डाबरी में मंगलवार को जीआरबी डिवीजन के 10-15 नक्सलियों की सूचना मिली थी।

इस पर हॉकफोर्स, सीआरपीएफ बी 207 और कोबरा की 12 टीमों ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। दोपहर करीब दो बजे हॉकफोर्स की टीम बिलालकसा जंगल में पहुंची। वहां मौजूद सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस टीम पर 20-30 राउंड फायरिंग की। जवानों ने पत्थर और पेड़ों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग की। इसके बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक नगेन्द्र सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में बड़ा सर्चिंग अभियान चल रहा है।

दिल्लीवासियों के लिए यूजर चार्ज समाप्त करने तथा हाउस टैक्स 5 वर्ष स्कीम देने की घोषणा का फेस्टा ने किया स्वागत

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह द्वारा दिल्लीवासियों के लिए यूजर चार्ज समाप्त करने तथा हाउस टैक्स 5 वर्ष स्कीम देने की घोषणा का फेडरेशन का सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा आप पार्टी के महापौर मैं यूजर टैक्स लगाने की घोषणा की थी
जिसको लेकर व्यापारियों सहित आम लोगों में काफी

गुस्सा था। इसको लेकर नव नियुक्त मेयर राजा इकबाल सिंह जी से फेडरेशन ने मुलाकात की थी और इसकी जानकारी दीजिए। जिसको लेकर राजा इकबाल सिंह जी ने व्यापारियों को FESTA TEAM को आश्वासन दिया था, वह जल्दी इस बारे में कोई निर्णय लेंगे। आज यह निर्णय आने से व्यापारियों में काफी खुशी है। हम व्यापारी भाजपा नेतृत्व का अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और महापौर जी धन्यवाद करते हैं।ये कमाल हुआ ट्रिपल इंजिन की सरकार का।

हॉरर-कॉमेडी 'कपकपी' के साथ दर्शकों को डराने आये तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और सिद्धि इदनानी

दिव्य दिल्ली : हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिद्धि इदनानी और सोनिया राठी अपनी आगामी फिल्म कपकपी के प्रचार के लिए दिल्ली आए। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयोजित किया गया था। फिल्म 23 मई 2025 को रिलीज होने वाली है।'कपकपी' हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन संगीत सिवन ने किया है, जिसका निर्देशन संगीथ सिवन और निर्माण जयेश पटेल ने जी स्टूडियोज और ब्रावो एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है। तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और सिद्धि इदनानी अभिनीत यह फिल्म 2023 की मलयालम फिल्म 'रोमांचम' की रीमेक है। फिल्म की पटकथा का रूपांतरण कुमार प्रियदर्शी और सौरभ आनंद ने किश है। प्रमोशनल इवेंट में मीडिया से बात करते हुए तुषार ने फिल्म के बारे में बताया, 'यह फिल्म लोगों की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, क्योंकि लोग डर के मारे अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देते हैं। इस फिल्म में कई मजेदार दृश्य हैं। हमारा मानना है कि फिल्म के दौरान भूतिया मजाक, प्रेत-बाधित हरकतें, जोरदार हंसी का झमेला, भूत का कराहना, लाइट्स का टिमटिमाना देखकर दर्शकों की चीखें हंसी में घुल जाएंगी। कॉमेडी को भयानक हॉरर के साथ मिलाते हुए 'कपकपी' एक भूतिया घर की डरावनी, लेकिन मजेदार दुनिया की झलक दिखाती है। यह डरावनी, पागल और बिल्कुल दीवानी कर देने वाली फिल्म है। कुल मिलाकर यह फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी।'सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिये बॉलीवुड की पसंदीदा कॉमिक जोड़ी श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर फिर से एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में तुषार कहते हैं, 'श्रेयस तलपड़े के साथ

ऑनस्क्रीन मेरी जोड़ी पहले भी दर्शकों को पसंद आई है और इस फिल्म में भी हमारी जबरदस्त कॉमिक केमिस्ट्री को दर्शक पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी ऑनस्क्रीन बॉन्डिंग इस अफरातफरी में एक पुरानी यादगार मिठास और बेहतरीन टाइमिंग को साथ लाएगी। हमारी जोड़ी इस डरावनी मस्ती में एक अतिरिक्त परत जोड़ेगी, जिससे 'कपकपी' इस सीजन की सबसे प्रत्याशित मनोरंजन में से एक बन गई है। कह सकते हैं कि यह फिल्म डर और मजा के बीच की महीन रेखा पर चलती है, और संगीत सिवन की कल्ट क्लासिक्स जैसे 'क्या कूल हैं हम' और 'अपना सपना मनी मनी' की पागलपन भरी ऊर्जा को भी सामने लाती है। यानी, 'कपकपी' आपकी मजाकिया हड्डियों को गुदगुदाते हुए आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए तैयार है।'फिल्म का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगीत सिवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके आखिरी प्रोजेक्ट में से एक है।

भारत ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में समावेशी ऊर्जा प्रशासन का आह्वान किया

नई दिल्ली
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने एक स्थायी और समावेशी ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की और अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना विषय के तहत ब्राजील के नेतृत्व की सराहना भी की। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने 19 मई को ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में उन्होंने वैश्विक विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और सामर्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। मनोहर लाल ने ब्रिक्स देशों को भारत में 2026 में आयोजित होने वाले अगले ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और वैश्विक दक्षिण के लिए ऊर्जा एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में ऊर्जा सुरक्षा को वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया तथा आर्थिक स्थिरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया।

तमिलनाडु सरकार ने शराब ठेकों पर ईडी के छापों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली
तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के शराब ठेकों पर ईडी के छापों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर चुका है। मद्रास हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिका खारिज करते हुए ईडी की कार्रवाई पर मुहर लगा दी थी। मद्रास हाई कोर्ट के इसी आदेश को मद्रास सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने 6 और 8 मार्च को खुदरा ठेकों पर छापे मारे थे। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ईडी ने उसके अधिकारियों को प्रताड़ित किया और छापे के दौरान घंटों हिरासत में रखा। ईडी के छापे राजनीतिक दुर्भावना की वजह से मारे गए।

लक्ष्मी तरू, युवा अग्रवाल समाज और ईआरडी फाउंडेशन ने बांटी दिव्यांगों को वीलचेयर

बिनोद कुमार
दिव्य दिल्ली : लक्ष्मी तरू फाउंडेशन, युवा अग्रवाल समाज त्रिनगर एवं ईआरडी केयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पशुर्राम भवन, शंकर चौक, त्रिनगर में दिव्यांगो के लिए वीलचेयर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था उन दिव्यांगजनों की सहायता करना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और व्हीलचेयर खरीदने में असमर्थ हैं। इस अभियान के अंतर्गत 14 जरूरतमंद दिव्यांगजनों को वीलचेयर वितरित की गई।का?क्रम में विपिन गर्ग ,संस्थापक लक्ष्मी तरू फाउंडेशन, सनी गोयल, चेयरमैन, युवा

अग्रवाल समाज त्रिनगर, निलेश गुप्ता, अध्यक्ष, युवा अग्रवाल समाज त्रिनगर, सौरभ गोयल महामंत्री युवा अग्रवाल समाज, त्रिनगर और संजीव भारद्वाज संस्थापक ईआरडी केयर फाउंडेशन की अहम भूमिका रही। मिडिया से बात करते हुए लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के संस्थापक विपिन गर्ग ने कहा यह एक प्रयास था दिव्यांगजनो के जीवन में उजाला लाने का, उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का। इस आयोजन ने न केवल मानवता की सच्ची सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि जब हाथ मदद के लिए बढ़ते हैं, तो ज़िंदगी की राह आसान हो जाती है। कार्यक्रम में अनेक सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें तिलकराम गुप्ता, विधायक, त्रिनगर विधानसभा, पूनम भारद्वाज, विधायक, वजीरपुर विधानसभा, मोहलाल गोड, अध्यक्ष, ब्राह्मण सभा त्रिनगर, पी. सी. गुप्ता, पूर्व प्रधान, अग्रवाल समाज त्रिनगर, चित्रा विद्यार्थी, निगम पार्षद, वजीरपुर, सत्येंद्र शर्मा विधायक प्रत्याशी, त्रिनगर कांग्रेस, मांगेराम बिंदल, समाजसेवी, राजिंदर गोले, समाजसेवी, पंकज शर्मा, उपाध्यक्ष, आदर्श नगर कांग्रेस, हरीश मित्तल, समाजसेवी, नरिंदर कौर, संस्थापक, सुरताज फाउंडेशन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आयोजकों ने यह संकल्प लिया कि वे आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यों को निरंतर करते रहेंगे, और समाज के हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397